प्रकाशन का गौरवाशाली 14वाँ वर्ष

दिव्य हिमगिरि

हिमालयी राज्यों की पहली साप्ताहिक पत्रिका

नज़र सब पर

वर्ष 14 | अंक 47 | मूल्य 15 रुपये | 13-19 अप्रैल, 2025

मोदी सरकार आतंकी तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत ले आई

ट्रंप की "टैरिफ नीति" से बिजनेस की दुनिया अशांत

EXPERIENCE HELI TOUR WITH

Himgiri
Aviation & Tourism

CHAR DHAM

Yatra By Helicoptor

5NIGHTS/6DAYS TOUR

Reserve your seat now

Contact for Reservation

8433456398, 9410353164 | Email: himgiritourism@gmail.com
6 Municipal Road, Opps. Bala hissar Academy, Dalanwala, Dehradun-248001 (UK)

वर्ष 14 | अंक 47

दिव्य हिमगिरि

13-19 अप्रैल, 2025

संपादक
कुँवर राज अस्थाना

वरिष्ठ संवाददाता
शंभूनाथ गौतम

ब्यूरो प्रमुख
मोनिका डबराल

विज्ञापन
पूनम आर्या

ग्राफिक डिजायनर
देव भट्ट

संवाददाता
हरिद्वार : डॉ. रजनीश गौतम
पौडी : रत्नमणि भट्ट
कोटद्वार : के.पी. बौंठियाल
रूद्रपुर : हेमचन्द्र बुडलाकोटी
चमोली : मुकेश रावत
रुड़की : श्रीगोपाल नारसन
नैनीताल : शीतल तिवारी
अल्मोड़ा : संजय कुमार अग्रवाल (एड.)
विकासनगर : अजय शर्मा
प्रसार : रमेश सिंह रावत

संपादकीय कार्यालय : 6, म्युनिसिपल रोड, बाला हिसार स्कूल के सामने, डालनवाला देहरादून (उत्तराखंड)
मोबाइल : +91 8433456398, 9410353164
Email: divyahimgiriddn@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक कुँवर बहादुर अस्थाना द्वारा सरस्वती प्रेस, 2, ग्रीन पार्क, निरंजनपुर, देहरादून से मुद्रित तथा 39/7 ई, ई. सी. रोड, (निकट मार्शल स्कूल सीनियर विंग) देहरादून-248001 उत्तराखण्ड से प्रकाशित। संपादक: कुँवर बहादुर अस्थाना*

*(पीआरबी एक्ट के तहत प्रकाशित सामग्री के लिए उत्तरदायी)

राज्यपाल को पहली बार सर्वोच्च न्यायालय ने सुनाई खरी-खरी

राज्य सरकारों और राज्यपालों के बीच तनातनी पुरानी बात है, पर यह पहली बार है जब सर्वोच्च न्यायालय ने किसी राज्यपाल को खरी-खरी सुनाते हुए उसके संवैधानिक कर्तव्यों और अधिकार क्षेत्र की सीमारेखा याद दिलाई है। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के राज्यपाल से कहा कि आप संविधान की शपथ लेते हैं। आपको किसी राजनीतिक दल की तरफ से संचालित नहीं होना चाहिए। आपको उत्प्रेरक बनना चाहिए, अवरोधक नहीं। न्यायालय की यह टिप्पणी एक तरह से उन सभी राज्यपालों को संबोधित है, जो चुनी हुई सरकारों के कामकाज में नाहक बाधा डालने की कोशिश करते हैं। तमिलनाडु सरकार ने करीब सवा साल पहले विधानसभा में बारह विधेयक पारित कराए थे। उन्हें मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा, पर उन्होंने उसमें से दो विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेज दिया और दस को वापस लौटा दिया। विधानसभा का विशेष सत्र बुला कर उन विधेयकों को दुबारा पारित करा लिया गया। मगर राज्यपाल ने उन्हें मंजूरी देने के बजाय अपने पास दबा कर रख लिया। यह मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा, तो उसने राज्यपाल के अधिकारों को रेखांकित करते हुए दुबारा पारित किए गए विधेयकों को मंजूरी देने और मुख्यमंत्री के साथ बैठ कर उनकी तकनीकी अड़चनों को दूर करने का निर्देश दिया था। मगर राज्यपाल ने उस निर्देश को भी नजरअंदाज कर दिया। वही मामला फिर सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा, तो दो न्यायाधीशों की पीठ ने उस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि वे सभी विधेयक उसी दिन से मंजूर माने जाएंगे, जिस दिन उन्हें दुबारा पारित किया गया था। राज्यपाल को तय सीमा के अंदर, मंत्रिपरिषद की सलाह के मुताबिक अपने विकल्पों पर विचार करना चाहिए, वरना उनके उठाए गए कदमों की कानूनी समीक्षा की जाएगी। न्यायालय की इस सख्त टिप्पणी की वजहें स्पष्ट हैं। पिछले कुछ वर्षों में न केवल तमिलनाडु, बल्कि उन तमाम राज्यों में, जहां केंद्र के विपक्षी दलों की सरकारें हैं, राज्यपाल अक्सर मुख्यमंत्री के साथ किसी पार्टी कार्यकर्ता की तरह उलझते देखे जाते रहे हैं। पश्चिम बंगाल, केरल, पंजाब, दिल्ली, झारखंड आदि राज्यों में अनेक मौकों पर चुनी हुई सरकार और राज्यपाल के अधिकारों को लेकर अप्रिय तकरार देखी जा चुकी है। पांच राज्यों की सरकारों ने सर्वोच्च न्यायालय से गुहार लगाई थी कि राज्यपाल उनके विधायी कामकाज में बेवजह अड़ंगा डालते हैं, विधानसभा में पारित विधेयकों को मंजूरी देने के बजाय उन्हें दबा कर बैठ जाते हैं। तब भी सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपालों को उनके पद की गरिमा और सांविधानिक दायित्वों का ध्यान दिलाया, मगर उनके कामकाज में कोई बदलाव नजर नहीं आया। यह प्रकट है कि राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है और जबसे इस पद पर सक्रिय राजनीति में रह चुके लोगों को नियुक्त किया जाने लगा है, वे राज्यपाल का दायित्व निभाने के बजाय किसी राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह दलीय प्रतिबद्धता जाहिर करते देखे जाते हैं। पिछले दस वर्षों में यह प्रवृत्ति कुछ अधिक बढ़ी है। जहां भी केंद्र के विपक्षी दलों की सरकारें हैं, वहां राज्यपाल सरकार के कामकाज में अवरोध पैदा करने का प्रयास करते देखे जाते हैं। राज्यपाल का अधिकार क्षेत्र राज्य सरकारों के कामकाज में सहयोग और उन्हें सांविधानिक मूल्यों के अनुरूप काम करने के लिए प्रेरित करने तक है, न कि राजनीतिक गतिविधियों में अनधिकार प्रवेश कर केंद्र की इच्छाओं को पोषित करना। सर्वोच्च न्यायालय की ताजा टिप्पणी इसी प्रवृत्ति पर प्रहार है। पर, राज्यपाल इसे कितनी गंभीरता से लेंगे, कहना मुश्किल है।

कुँवर राज अस्थाना

शराब सस्ती, बिजली, पानी और शिक्षा महंगीः यशपाल आर्य

यशपाल आर्य
नेता प्रतिपक्ष

यशपाल आर्य, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार के अजीबोगरीब निर्णयों से आने वाले वर्ष में राज्य में शराब सस्ती हो रही है और आम आदमी की प्राथमिक जरूरत बिजली-पानी-पढ़ाई महंगी होती जा रही है।

उन्होंने कहा कि आज फिर राज्य विद्युत नियामक आयोग ने उत्तराखंड उर्जा निगम के बिजली की दरों में 5.62 ।ीसदी तक की बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव को स्वीखृत कर आम उपभोद्राओं को महंगाई का करंट दिया है ,इससे प्रदेश के 27 लाख उपभोद्रा प्रभावित होंगे। एक तरु ऊर्जा प्रदेश उत्तराखंड में बिजली के दाम भी बढ़ गए हैं और कटौती भी। ग्रामीण क्षेत्रें समेत छोटे शहरों में प्रतिदिन ङ्ख से ल्ष घंटे तक बिजली कटौती हो रही है।

श्री आर्य ने कहा कि अघोषित बिजली कटौती से जनता त्रहिमाम कर रही है, 24 घण्टे लो वोल्टिज और बार बार ट्रिपिंग की समस्या से जनता बेहाल है। उत्तराखंड बिजली उत्पादन कर रहा है पर इसका लाभ दूसरे प्रदेश के लोगों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले अप्रैल से लेकर हाल की बृ) तक एक साल के भीतर दूसरी बार बिजली की कीमतें बढ़ाकर सरकार ने ये सि) कर दिया है कि वह जनता को लूटने का कोई अवसर नहीं गँवायेगी।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पिछले एक वर्ष के अन्तराल में आम जरूरत की चीजों के दामों कई गुना बढ गए हैं। आम जरूरत की चीजों के दामों को नियंत्रि रखना केन्द्र व राज्य सरकार के बस में नही रह गया है। राष्ट्रीय स्तर पर रसोई गैस, पेट्रोलियम पदार्थ तथा खाद्य पदार्थों के लगातार बढ़ रहे दामों के बाद राज्य सरकार द्वारा बिजली की दरों में भारी वृ) कर जनता को मंहगाई के दोहरे बोझ से लादने का काम किया जा रहा है।

सामाजिक बदलाव के महान व्यक्तित्व डॉ. भीमराव आंबेडकर

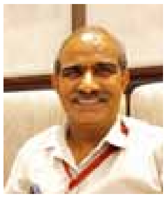

डॉ श्रीगोपाल नारसन
एडवोकेट

भारतीय संविधान के निर्माता एवं सामाजिक चिंतक डॉ. बाबा साहेब भीम राव आंबेडकर की अद्वितीय प्रतिभा देश व समाज के लिए अनुकरणीय रही है। वे एक प्रख्यात मनीषी, समाज सेवक, महानायक, विधि विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, एवं धैर्यवान बौद्धिक व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने अपना जीवन समग्र भारत के कल्याण कामना हेतु उत्सर्ग कर दिया था। विशेषकर 80 प्रतिशत उन दलित, सामाजिक व आर्थिक तौर से अभिशप्त लोगो के लिए, जिन्हें शोषण व पिछड़ेपन के अभिशाप से मुक्ति दिलाना ही डॉ. आंबेडकर का जीवन संकल्प रहा, जिसमे वे सफल भी रहे।

सामाजिक चिंतक डॉ. भीमराव आंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 को महू में सूबेदार रामजी शकपाल एवं भीमाबाई की चौदहवीं संतान के रूप में हुआ था। बचपन से ही उनके व्यक्तित्व में स्मरण शक्ति की प्रखरता, बुद्धिमत्ता, ईमानदारी, सच्चाई, नियमितता, दृढ़ता का प्रभाव रहा। डॉ भीमराव सातारा गांव के एक ब्राह्मण शिक्षक को बेहद प्रिय रहे। ये शिक्षक ही डॉ. आंबेडकर के लिए उनपर सामाजिक अत्याचार और लांछन की तेज धूप में बादल रूपी छांव बन गए थे। डॉ. आंबेडकर की सोच थी कि, 'समाज को श्रेणीविहीन और वर्णविहीन करना होगा क्योंकि श्रेणी ने इंसान को दरिद्र और वर्ण ने इंसान को दलित बना दिया है। जिनके पास कुछ भी नहीं है, वे लोग दरिद्र माने गए और जो लोग कुछ भी नहीं है, वे दलित समझे जाते थे।'

बाबा साहेब ने इसी भेदभाव के प्रति संघर्ष का बिगुल बजाकर समाज को जागरूक करने की कोशिश की। वे कहते थे कि, 'छीने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते, अधिकार वसूल करना होता है।' उन्होंने कहा था, 'हिन्दुत्व की गौरव वृद्धि में वशिष्ठ जैसे ब्राह्मण, राम जैसे क्षत्रिय, हर्ष की तरह वैश्य और तुकाराम जैसे शूद्र लोगों ने अपनी साधना का प्रतिफल जोड़ा है। उनका हिन्दुत्व दीवारों में घिरा हुआ नहीं है, बल्कि ग्रहिष्णु, सहिष्णु व चलिष्णु है। 'बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने भीमराव आंबेडकर को मेधावी छात्र के नाते छात्रवृत्ति देकर सन 1913 में विदेश में उच्च शिक्षा के लिए भेज दिया था। उन्होंने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, दर्शन और अर्थ नीति का अध्ययन किया और विद्वता हासिल की। चूंकि विदेश में भारतीय समाज का अभिशाप और जन्मसूत्र से प्राप्त अस्पृश्यता की कालिख नहीं थी। इसलिए उन्होंने अमेरिका में एक नई दुनिया के दर्शन किए। बाबासाहेब अम्बेडकर की विद्वता का प्रमाण यह है कि वे 64 विषयों में मास्टर थे। वे हिन्दी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, पर्शियन और गुजराती जैसे 9 भाषाओँ के जानकार थे। उन्होंने 21 साल तक विश्व के सभी धर्मो को लेकर तुलनात्मक अध्ययन किया था।

बाबासाहेब ने लंदन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स में 8 वर्ष में समाप्त होनेवाली पढाई मात्र 2 वर्ष 3 महीने में पूरी की। इसके लिए उन्होंने प्रतिदिन 21-21 घंटे पढ़ाई की थी। डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर का अपने 8,50,000 समर्थको के साथ बौद्ध धर्म में दीक्षा लेना विश्व में एक ऐतिहासिक घटना थी, क्योंकि यह विश्व का सबसे बडा धर्मांतरण था। बाबासाहेब को बौद्ध धर्म की दीक्षा देनेवाले महान बौद्ध भिक्षु 'महंत वीर चंद्रमणी' ने उन्हें ''इस युग का आधुनिक बुद्ध'' कहा था।

लंदन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स से ''डॉक्टर ऑल सायन्स'' नामक अनमोल डॉक्टरेट पदवी प्राप्त करनेवाले बाबासाहेब विश्व के पहले और एकमात्र महापुरूष रहे हैं। डॉ. आंबेडकर ने अमेरिका की एक सेमिनार में 'भारतीय जाति विभाजन' पर अपना मशहूर शोध-पत्र पढ़ा, जिसमें उनके व्यक्तित्व की खूब प्रशंसा हुई।

सर्वसम्मति से डॉ. आंबेडकर को संविधान सभा की प्रारूपण समिति का अध्यक्ष चुना गया। 26 नवंबर सन 1949 को डॉ. आंबेडकर के नेतृत्व में (315 अनुच्छेद का) भारतीय संविधान पारित हुआ।

ट्रंप की 'टैरिफ नीति' से बिजनेस की दुनिया अशांत

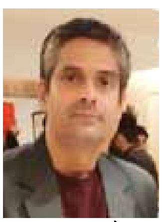

शंभू नाथ गौतम
वरिष्ठ पत्रकार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 'आक्रामक टैरिफ नीति' से दुनिया में हलचल मची हुई है। ट्रंप ने सबसे ज्यादा टैरिफ चीन पर लगाया है। जिसके बाद ड्रैगन तिलमिलाया हुआ है। चीन और अमेरिका के बीच चल रहे टैरिफ वॉर दुनिया के लिए सिरदर्द बन गया है। टैरिफ को लेकर दोनों देशों के संबंध बेहद तनावपूर्ण हैं। अमेरिका के 145% टैरिफ के जवाब में अब चीन ने 125% टैरिफ लगाया दिया है। वहीं ट्रंप की राहत ने भारत को चैन की सांस जरूर दी है। ट्रेड वॉर के बीच चीन की कई इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों ने भारतीय कंपनियों को 5% तक की छूट ऑफर की है। इससे भारत में टीवी, फ्रिज, स्मार्टफोन जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स सस्ते हो सकते हैं। चीन से भारत सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आयात करता है।

दुनिया में इन दिनों एक ऐसा युद्ध हो रहा है जिसमें हथियार, हवाई हमले, आतंकी वारदात और सीमा विवाद भी नहीं है। फिर भी कई देशों में उथल-पुथल मची हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने करीब 100 देशों पर लगाई गई 'आक्रामक टैरिफ नीति' ने बिजनेस की दुनिया को अशांत कर दिया है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने बाद में 75 देशों को राहत भी दी। लेकिन ट्रंप के इस कदम के बाद दुनिया में हलचल मची हुई है। अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप राजनीति के साथ बिजनेस के मैदान में भी खुलकर आ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति से दुनिया के शक्तिशाली देश अमेरिका और चीन के बीच खुलकर ट्रेड वॉर शुरू हो गया है। चीन और अमेरिका के बीच चल रहे टैरिफ वॉर पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द बन गया है। टैरिफ को लेकर अमेरिका और चीन के संबंध बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि अमेरिका दुनिया को अपने अनुसार चलाने का प्रयास करता रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति से अमेरिका सहित विश्व अर्थव्यवस्था में मंदी आ सकती है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ नीति ने भारत समेत पूरी दुनिया की मेटल इंडस्ट्री में हड़कंप मचा दिया है। अमेरिका ने हाल ही में 'रेसिप्रोकल टैरिफ' लागू कर एक बड़ा कदम उठाया। इस नीति के तहत भारत से अमेरिका को जाने वाले मेटल उत्पादों पर अब 26% टैरिफ लगाया गया है, जबकि पहले यह दर केवल 1.8% थी। दूसरी तरफ, अमेरिका से भारत आने वाले मेटल उत्पादों पर भारत पहले से ही 9.6% शुल्क लगाता है। मूल बात यह है कि टैरिफ बढ़ाने से अमेरिकी अर्थव्यवस्था में उत्पादन करना अधिक लाभप्रद हो जाएगा। घरेलू उत्पादन बढ़ने से वहां पर श्रमिकों की मांग बढ़ेगी और श्रमिकों के वेतन भी बढ़ेंगे। अमेरिका में एक्साइज डयूटी एवं आयात कर की वसूली बढ़ेगी। घरेलू कंपनियों का लाभ बढ़ेगा। वे अधिक कर अदा करेंगी। इन सब कारणों से अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने दो अप्रैल को करीब 100 देशों पर टैरिफ लगाने के 7 दिन बाद ही उन्होंने इस फैसले पर 90 दिनों की रोक लगा दी है। जबकि 11 अप्रैल को चीन पर 145% टैरिफ लगाकर तगड़ा झटका दिया है। ट्रंप ने बुधवार को भारत समेत 75 देशों को बड़ी राहत देने का काम किया। उनकी तरफ से बढ़े हुए

अमेरिका के भारत को राहत दिए जाने के बावजूद केंद्र सरकार बाजार में निगाह बनाए हुए

अमेरिका और चीन के बीच में काफी व्यापार होता है, दोनों ही देश एक दूसरे पर कई चीजों के लिए निर्भर हैं। ऐसे में ट्रेड वॉर की वजह से आर्थिक मंदी का खतरा मंडराने लगा है। इस बीच ट्रंप की राहत ने भारत जैसे देशों को चैन की सांस जरूर दे दी है। माना जा रहा है कि भारत ने रणनीति के तहत अमेरिका पर जवाबी टैरिफ नहीं लगाया था, इसके बजाय बातचीत का चैनल खोला गया। अब इसी का नतीजा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को राहत दे दी है। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा छेड़े गए वैश्विक टैरिफ युद्ध के बीच, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के लिए बातचीत कर रहा है, उन्होंने जोर देकर कहा कि देश के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी और दबाव में कोई बातचीत नहीं की जाएगी। पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि भारत प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर अमेरिका के साथ लगातार बातचीत कर रहा है तथा देश के हितों की रक्षा करेगा, उन्होंने कहा कि नई दिल्ली कभी भी बंदूक की नोक पर बातचीत नहीं करता। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका द्वारा लागू की गई नई टैरिफ पॉलिसी ने भारत के लिए वैश्विक निर्यात के नए अवसर पैदा किए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में भारत को अपने निर्यात क्षमता को बढ़ाने का सुनहरा मौका मिला है। गडकरी ने कहा कि दुनिया भर में जिस तरह के व्यापारिक परिवर्तन हो रहे हैं, उसमें भारत के पास अवसर है कि वह अमेरिका और यूरोप जैसे बाजारों में चीन की जगह ले सके। गडकरी ने बताया कि भारत में लॉजिस्टिक्स का खर्च अभी भी 14 से 16 प्रतिशत है, जबकि चीन में यह केवल 8 प्रतिशत है। यह लागत का अंतर भारत को निर्यात के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा में पीछे कर देता है। उन्होंने कहा कि सरकार इस खर्च को घटाने के लिए देशभर में लॉजिस्टिक्स पार्क, मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, और अन्य बुनियादी ढांचागत सुविधाओं को विकसित कर रही है। अमेरिका की आक्रामक टैरिफ नीति और वैश्विक मंदी का खतरा अभी भी मंडरा रहा है। अगर वैश्विक मांग और ज्यादा गिरती है तो मेटल सेक्टर के लिए यह साल काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

टैरिफ पर 90 दिनों की रोक लगा दी गई। साथ ही इन देशों पर 10% का बेसलाइन टैरिफ लगा दिया। इन 75 देशों में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ताइवान, वियतनाम जैसे देश शामिल हैं, लेकिन चीन को लेकर उनका स्टैंड स्पष्ट दिखा, वहां और ज्यादा टैरिफ लगाया गया।

अमेरिका और चीन के बीच बढ़ता जा रहा टैरिफ वॉर

डोनाल्ड ट्रंप की इस नीति के बाद चीन ने भी अमेरिका को करारा जवाब दिया है। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर बढ़ता जा रहा है। अमेरिका की तरफ से लगाए गए भारी-भरकम टैरिफ के बाद चीन बाकी देशों से भी संपर्क कर रहा है। वह अमेरिका की नई रणनीति से निपटने के लिए एक संयुक्त मोर्चा बनाने की कोशिश में है। हालांकि, इसमे उसे खास सफलता नहीं मिल रही है, क्योंकि कई देश ट्रंप के खिलाफ नए गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं हैं। चीन ने इस मुद्दे पर बातचीत करने से इनकार करते हुए एलान किया है कि वह आखिर तक लड़ेगा। अमेरिका के 145% टैरिफ के जवाब में अब चीन ने 125% टैरिफ लगाया दिया है। ये शनिवार 12 अप्रैल से लागू हो गया। चीन ने कहा है कि अब वह अमेरिका की तरफ से लगाए जाने वाले किसी भी अतिरिक्त टैरिफ का जवाब नहीं देगा। चीन ने कहा कि अमेरिका की तरफ से लगाए गए असामान्य टैरिफ अंतरराष्ट्रीय और आर्थिक व्यापार नियमों का गंभीर रूप से उल्लंघन करते हैं। यह पूरी तरह से एकतरफा दबाव और धमकाने की नीति है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि चीन किसी से डरता नहीं है। पिछले 70 साल में हुआ चीन का विकास कड़ी मेहनत और खुद पर निर्भर रहने का नतीजा है। जिनपिंग ने कहा कि चीन कभी दूसरों के दान के भरोसे नहीं रहा है। न ही कभी किसी की जबरदस्ती से डरा है। दुनिया कितनी भी क्यों न बदल जाए, चीन परेशान नहीं होगा। जिनपिंग ने कहा कि ट्रेड वॉर में कोई विजेता नहीं होता। दुनिया के खिलाफ जाने का मतलब खुद के खिलाफ जाना है। चीन-अमेरिका के बीच जारी ट्रेड वॉर के बीच चीन की कई इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों ने भारतीय कंपनियों को 5% तक की छूट ऑफर की है। इससे भारत में टीवी, फ्रिज, स्मार्टफोन जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स सस्ते हो सकते हैं। चीन से भारत सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आयात करता है। अमेरिका के चीन पर 145% टैरिफ लगाने का आसान भाषा में मतलब है कि चीन में बना 100 डॉलर का सामान अब अमेरिका में जाकर 225 डॉलर का हो जाएगा। अमेरिका में चीनी सामानों के महंगे होने से उनकी डिमांड घटेगी और बिक्री कम हो जाएगी।

किसी भी देश की सरकार अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए लगाती है टैरिफ

आइए जानते हैं टैरिफ क्या होता है और एक देश उसे दूसरे देशों पर क्यों लगता है। मान लीजिए आपके देश में कोई विदेशी सामान बहुत सस्ती मिल रही है और उसी वस्तु को स्थानीय कंपनी महंगे दाम पर बेच रही है। ऐसे में विदेशी माल से मुकाबला करना घरेलू कंपनियों के लिए मुश्किल हो जाता है। यहां की सरकार 'टैरिफ' नाम का एक आर्थिक हथियार इस्तेमाल करती है, जो दरअसल एक आयात शुल्क है। यानी जब कोई वस्तु विदेश से आपके देश में आती है, तो उस पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जाता है, जिससे वो वस्तु महंगी हो जाए और घरेलू उत्पादों को बराबरी का मौका मिल सके। टैरिफ एक प्रकार का कर (टैक्स) है जो किसी देश द्वारा आयातित वस्तुओं (इम्पोर्टेड गुड्स) पर लगाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार के लिए राजस्व (रेवेन्यू) बढ़ाना और घरेलू कंपनियों (डोमेस्टिक कंपनी) को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना होता है। टैरिफ लगाने का मुख्य उद्देश्य घरेलू उद्योगों को संरक्षण देना है। यह नीति उन देशों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने व्यापार घाटे को कम करना चाहते हैं। कई देश अपने स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आयातित सामानों पर ऊंचे टैरिफ लगाते हैं, लेकिन बदले में वे अपने सामानों को कम टैरिफ पर निर्यात करना चाहते हैं। टैरिफ लगने से विदेशी सामान महंगे हो जाते हैं, जिससे लोग स्थानीय उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित होते हैं। यह वैश्विक व्यापार में तनाव बढ़ा सकता है। जवाबी टैरिफ का मूल अर्थ व्यापार में निष्पक्षता लाना है।

मोदी सरकार आतंकी तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत ले आई

2008 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड 64 साल के तहव्वुर राणा को 10 अप्रैल को स्पेशल विमान से अमेरिका से भारत लाया गया। राणा को अमेरिका से भारत लाना बिल्कुल भी आसान नहीं था बल्कि कई स्तर पर कठिन से कठिनतम चुनौतियों का सामना करना पड़ा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मुख्य आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा का प्रत्यर्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की बड़ी सफलता है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि तहव्वुर राणा को भारत लाने की प्रक्रिया की शुरुआत कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने की थी और इसे रणनीतिक रूप से आगे बढ़ाया। एनडीए सरकार ने इस मामले में कुछ नहीं किया और यह बस उस प्रक्रिया का फल है, जिसे यूपीए सरकार ने शुरू किया था।

17 साल बाद मुंबई हमलों का आरोपी आतंकी तहव्वुर राणा अमेरिका से भारत ले आया गया। 2008 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड 64 साल के तहव्वुर राणा को 10 अप्रैल को स्पेशल विमान से अमेरिका से भारत लाया गया। इस आतंकी को भारत लाने में पूरा श्रेय मोदी सरकार का है। राणा को अमेरिका से भारत लाना बिल्कुल भी आसान नहीं था बल्कि कई स्तर पर कठिन से कठिनतम चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना ठान लेने पर क्या नहीं मिलता। भारत को राणा भी मिल गया। इसके लिए भारत सरकार के दो मंत्रालयों के साथ-साथ विभिन्न एजेंसियों ने तालमेल का शानदार उदाहरण पेश किया। गुरुवार को खास फ्लाइट से राणा की दिल्ली में लैंडिंग हुई और इसके साथ ही भारत की आतंकवाद के खिलाफ जंग को एक बड़ी जीत मिली है।

प्रत्यर्पण में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के सामने एक और बड़ी चुनौती थी, वह थी ऑपरेशन राणा की भनक पाकिस्तान स्थित आतंकवादी गुटों को न लगने देना। इस मिशन के लिए भारतीय-अमेरिकी खुफिया एजेंसियों, एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट ने फ्लाइट पर रियल टाइम नजर बनाए रखी, ताकि किसी भी मूवमेंट को आसानी से ट्रैक कर सकें। उसे अमेरिका से प्रत्यर्पित करके भारत लाने में मोदी सरकार का संकल्प का जाहिर होता है। अमेरिकी सरकार ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण से जुड़ी सभी कानूनी अड़चनों को सुलझाने के बाद तुरंत उसे भारत भेजने का फैसला लिया था। फरवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वॉशिंगटन में मुलाकात के दौरान, ट्रंप ने राणा को 'एक बेहद खतरनाक आदमी' बताते हुए कहा था कि उनकी सरकार ने राणा को भारत को सौंपने की मंजूरी दे दी है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राणा की आखिरी अपील भी खारिज कर दी थी, जिसमें उसने भारत प्रत्यर्पित होने से रोकने की गुहार लगाई थी। राणा ने अपनी अपील में कहा था कि उसे भारत भेजा जाना अमेरिकी कानून और संयुक्त राष्ट्र के टॉर्चर विरोधी कन्वेंशन का उल्लंघन होगा, क्योंकि भारत में उसे शारीरिक यातना दी जा सकती है। लेकिन अमेरिका की अदालत ने उसकी यह दलील मानने से साफ इनकार कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मुख्य आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा का प्रत्यर्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की बड़ी सफलता है। उन्होंने कहा कि उसे यहां लाया जाएगा और उसे सजा दी जाएगी। अमित शाह ने कांग्रेस का नाम लिए बिना उस पर भी कटाक्ष किया और कहा कि 2008 में मुंबई आतंकी हमले के समय सत्ता में बैठे लोग राणा को मुकदमे का सामना करने के लिए भारत नहीं ला सके। वहीं कांग्रेस का कहना है कि तहव्वुर राणा को भारत लाने की प्रक्रिया की शुरुआत कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने की थी और इसे रणनीतिक रूप से आगे बढ़ाया। एनडीए सरकार ने इस मामले में कुछ नहीं किया और यह बस उस प्रक्रिया का फल है, जिसे यूपीए सरकार ने शुरू किया था। शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को लेकर कहा, 'ये लोग तहव्वुर का फेस्टिवल मना रहे हैं। पकिस्तान के जेल में कुलभूषण जाधव सड़ रहा है, उसे लेकर आइए। दाऊद इब्राहिम को लेकर आइए। जब तक बिहार का चुनाव होगा तब तक ये देश में तहव्वुर राणा फेस्टिवल मनाएंगे।

मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को दहला दिया था

मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को दहला दिया था। इस हमले में 10 आतंकवादी समुद्र के रास्ते मुंबई में घुसे और फिर रेलवे स्टेशन, दो बड़े होटल और एक यहूदी सेंटर में हमला कर दिया। इस धमाके में 166 लोगों की जान चली गई, कइयों का घर उजड़ गया, कई अनाथ हो गए तो कई जिंदगी भर के लिए अपाहिज

हो गए। करीब 60 घंटे तक पूरी मुंबई दहशत में डूबी रही।

इस हमले में इकलौता जिंदा बचे अजमल कसाब को 2012 में पुणे के यरवदा जेल में फांसी पर चढ़ा दिया गया था। इतने बड़े हमले की सजा कसाब को तो मिल गई थी, पर तहव्वुर राणा जैसे गुनहगार आजाद घूम रहे थे। अब भारत को आखिरकार राणा मिल गया है, तो मुंबई हमले के पीड़ितों को इंसाफ की उम्मीद है। वहीं पाक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने कहा कि तहव्वुर राणा ने पिछले दो दशकों से अपने पाकिस्तानी दस्तावेजों को रिन्यू नहीं कराया है। उसके पास कनाडा का नागरिकता है। गौरतलब है कि पाकिस्तान अपने उन नागरिकों को दोहरी नागरिकता रखने की अनुमति देता है जो कनाडा में जाकर बस गए हैं। तहव्वुर राणा को 2009 में एफबीआई ने गिरफ्तार किया था। राणा को अमेरिका में लश्कर-ए-तैयबा का समर्थन करने के लिए दोषी ठहराया गया था। अब तक वह लॉस एंजिल्स के एक डिटेंशन सेंटर में बंद था। राणा को भारत लाने को लेकर बुधवार को होम मिनिस्ट्री में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मीटिंग की।

केदारनाथ धाम के पहले चरण के लिए हेलीकॉप्टर सेवा हुई फुल

इस साल चार धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की डिमांड बढ़ गई है। केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर बुकिंग सेवा 31 मई तक फुल हो गई है। 8 अप्रैल को आईआरसीटीसी ने 12 बजे बुकिंग के लिए वेबसाइट खोली थी। वेबसाइट खुलते ही मात्र 5 घंटे में 31 मई तक के लिए टिकट फुल हो गए हैं। पहले चरण के लिए यूकाडा ने 8 अप्रैल से 31 मई तक के लिए हेलीकॉप्टर बुकिंग शुरू की थी। ऐसे में अब 31 मई तक किसी भी दिन के लिए टिकट उपलब्ध नहीं है। केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाएं 2 मई से शुरू होंगी, जब धाम के कपाट खुलेंगे। धामी सरकार ने चार धाम यात्रा की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। यात्रा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए राज्य सरकार ने 6 जिलों को धनराशि भी आवंटित कर दी है।

इसी महीने 30 अप्रैल से शुरू होने वाली चार धाम यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ उमड़ने जा रही है। यह अनुमान इसलिए लगाया जा रहा है कि अभी तक चार धाम यात्रा के लिए 16 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं। अभी फिलहाल ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं खुले हैं। ऐसे ही हेलीकॉप्टर से चार धाम जाने वाले यात्रियों ने अभी तक बंपर बुकिंग कर ली है। सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम जाने के लिए हेलीकॉप्टर में बुकिंग की गई है। केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर बुकिंग सेवा 31 मई तक फुल हो गई है। 8 अप्रैल को आईआरसीटीसी ने 12 बजे बुकिंग के लिए वेबसाइट खोली थी। वेबसाइट खुलते ही मात्र 5 घंटे में 31 मई तक के लिए टिकट फुल हो गए हैं। पहले चरण के लिए यूकाडा ने 8 अप्रैल से 31 मई तक के लिए हेलीकॉप्टर बुकिंग शुरू की थी। ऐसे में अब 31 मई तक किसी भी दिन के लिए टिकट उपलब्ध नहीं है। बता दें कि आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर पहले ही दिन 7650 टिकटों की बुकिंग हुई। जिसमें यात्रियों की संख्या 23150 है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि चारधाम यात्रा को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। यूकाडा की सीईओ सोनिका ने कहा कि 31 मई से आगे की बुकिंग के लिए जल्द ही नई तारीख का एलान किया जाएगा। ताकि जो यात्री टिकट बुकिंग से छूट गए हैं, वह हेलीकॉप्टर की टिकट बुकिंग कर सकें। उन्होंने बताया कि इस साल हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग में पूरी तरह से प्रदर्शित अपनाई गई है। हर एक यात्री को टिकट बुकिंग में अपने सारे दस्तावेज और यात्रा का रजिस्ट्रेशन देना अनिवार्य होगा। केदारनाथ के लिए लगभग 7 हेलीकॉप्टर कंपनियां सेवाएं दे रही हैं। जो गुप्तकाशी, सिरसी और फाटा से उड़ान भर यात्रियों को केदारनाथ पहुंचते हैं। यात्रा करने के लिए बड़ी संख्या में लोग हेलीकॉप्टर सेवा का फायदा उठाते हैं। चारधाम यात्रा के लिए धामों के कपाट खुलने की तिथि तय की जा चुकी है। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल, केदारनाथ धाम के कपाट दो मई और बदरीनाथ धाम के कपाट चार मई को खुलेंगे। श्री हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को खुलेंगे।

चार धाम यात्रा में साइबर ठगों से बचाने के लिए पुलिस की विशेष नजर

चार धाम यात्रा के लिए धामी सरकार तीर्थ यात्रियों की सुविधा को देखते हुए हर दिन कुछ न कुछ नया निर्देश जारी कर रही है। अभी तक यात्री ऑनलाइन में ही अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। चार धाम यात्रा शुरू होने से 3 दिन पहले धामी सरकार ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू करेगी। इस बार श्रद्धालुओं के लिए 60 ऑफलाइन काउंटर खुलेंगे। इस बार काउंटरों की संख्या दोगुनी से भी ज्यादा की जा रही है। ताकि बिना पंजीकरण आने वाले श्रद्धालुओं को ज्यादा परेशानी न हो। चार धाम यात्रा पर जाने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। चारों धामों की धारण क्षमता के अनुसार श्रद्धालुओं के लिए 60% ऑनलाइन पंजीकरण किए जा रहे हैं। जबकि 40% पंजीकरण ऑफलाइन होगे। यह पंजीकरण सेंटर हरिद्वार, ऋषिकेश और विकास नगर में खोले जाएंगे। यात्रा शुरू होने पर बाहरी राज्यों से बड़ी संख्या में बिना पंजीकरण के श्रद्धालु आते हैं। जिन्हें रजिस्ट्रेशन करने में काफी

दिक्कत होती है। इसलिए सरकार ने इस बार पंजीकरण काउंटर बढ़ाने का निर्णय लिया है। हर साल की तरह इस बार भी बाबा केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। हालांकि, यात्रा शुरू होने से पहले ही साइबर ठग सक्रिय हो गए हैं। इस बार साइबर पुलिस और उत्तराखंड नागरिक उड्यन विकास प्राधिकरण (यूकाडा) ने इनसे निपटने के लिए कमर कस ली है। पुलिस और यूकाडा द्वारा हेली सेवाएं व अन्य बुकिंग के लिए यात्रियों से आधिकारिक वेबसाइट का प्रयोग करने की सलाह दी गई है।

यात्री उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ही बुकिंग करें

हर साल केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए हेली सेवाओं का संचालन होता है, लेकिन फर्जी वेबसाइट्स और स्कैमर्स यात्रियों को ठगने में जुट जाते हैं। इसे रोकने के लिए उत्तराखंड साइबर सेल ने प्राथमिकता के आधार पर कई कदम उठाए हैं। वहीं, साइबर पुलिस ने अपील की है कि यात्री केवल उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ही बुकिंग करें। पिछले साल चारधाम यात्रा के नाम पर ठगी करने वाली 80 फर्जी वेबसाइट्स को बंद किया गया था और 30 से अधिक फेक फेसबुक विज्ञापनों को हटाया गया था। इसके अलावा, 50 से ज्यादा बैंक खातों को फ्रीज किया गया था। साइबर पुलिस ने कई ठगों को गिरफ्तार भी किया, जिनके पास से मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद हुए। पुलिस ने यात्रियों से आग्रह किया है कि ऑनलाइन आधार कार्ड या पैन कार्ड जैसी संवेदनशील जानकारी किसी के साथ शेयर न करें। प्रशासन और पुलिस की सतर्कता से उम्मीद है कि इस बार यात्रा सुचारु और सुरक्षित रहेगी। पुलिस प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि टिकट बुकिंग से पहले वेबसाइट की प्रामाणिकता जांच लें और किसी भी संदेह की स्थिति में तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क करें।

बदरीनाथ और केदारनाथ धाम में होने वाली पूजाओं की ऑनलाइन बुकिंग शुरू

चार धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन बुकिंग चल रही है। वहीं पहले चरण में हेलीकॉप्टर सेवा के लिए भी बुकिंग फुल हो चुकी है। बदरीनाथ और केदारनाथ धाम में होने वाली पूजाओं की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है। श्रद्धालु 10 अप्रैल से पूजा की बुकिंग बद्री-केदार मंदिर समिति की वेबसाइट www.badrinath-kedarnath.gov.in पर कर सकते है। बीकेटीसी के मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल ने यह जानकारी दी है। जो श्रद्धालु उत्तराखंड के धामों तक नहीं आ सकते हैं और घर बैठे ही केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में अपने नाम से पूजा करवाना चाहते हैं, वो केदारनाथ मंदिर समिति ने 30 जून तक के लिए ऑनलाइन पूजा बुकिंग की सुविधा शुरू की है। श्रद्धालु वेबसाइट पर जाकर प्रातःकालीन, सायंकालीन और विशेष पूजा बुक कर सकते हैं। इस बार पूजाओं के शुल्क में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उसमें किसी भी तरह की कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गयी है। श्री बदरीनाथ धाम की पूजाओं में अभिषेक, महाभिषेक पूजा, वेदपाठ, गीता पाठ, विष्णुसहस्त्रनाम पूजा, चांदी आरती, स्वर्ण आरती, गीत गोविंद पाठ शयन आरती शामिल है। इसी तरह भगवान केदारनाथ की पूआओं में रुद्राभिषेक पूजा,लघु रुद्राभिषेक महामृत्युंजय पाठ, षोडशोपचार पूजा, शायं कालीन आरती आदि शामिल है। गुरुवार को मंदिर समिति की वेबसाइट पर 93 पूजा आनलाइन बुक हुई है। जिसमें बदरीनाथ के लिए कुल 32 महाभिषेक और अभिषेक पूजा बुकिंग की गई है। जबकि केदारनाथ के लिए 61 षोडशोपचार पूजा बुक हुई है। इस साल बदरीनाथ धाम के लिए तीस फीसदी और केदारनाथ के लिए बीस फीसदी पूजाएं ऑनलाइन बुक हो रही है। अक्षय तृतीया यानी 30 अप्रैल के दिन श्रद्धालुओं के लिए गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। इसके साथ उत्तराखंड चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। 2 मई को केदारनाथ धाम और 4 मई को बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। लोगों में तीर्थ यात्रा को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड में आते हैं। केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में अपने नाम से ऑनलाइन पूजा कराए जाने की प्रक्रिया कपाट खुलने के बाद शुरू हो जाएगी, जबकि ऑनलाइन पूजा कराए जाने से संबंधित रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 10 अप्रैल से शुरू हो गई है।

चार धाम यात्रा के लिए राज्य सरकार ने 6 जिलों को धनराशि आवंटित की

चार धाम यात्रा की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। यात्रा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए राज्य सरकार ने 6 जिलों को धनराशि भी आवंटित कर दी है। इसके तहत हरिद्वार, टिहरी और देहरादून जिला प्रशासन को एक-एक करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। यात्रा मार्ग के प्रमुख जिले चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिला प्रशासन को तीन-तीन करोड रुपए जारी किए गए हैं। पौड़ी जिला प्रशासन को 50 लाख और गढ़वाल आयुक्त को 25 लाख रुपए जारी किए गए हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि 30 अप्रैल से चारधाम शुरू हो रही है। यात्रा के लिए सभी विभाग तैयारी लगभग पूरी कर चुके हैं। पिछले सालों की कमियों से सीख लेकर सरकार इस बार यात्रा की तैयारी और बेहतर कर रही है। उन्होंने बताया कि इस बार हेलीकॉप्टर बुकिंग की कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं इसके साथ ही यात्रा मार्गो पर पार्किंग के दौरान गलत तरह से शुल्क वसूली करने पर भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पर्यटन विकास परिषद में स्टेट लेवल का कंट्रोल रूम बनाया गया है जो 24 घंटे काम करेगा इसके लिए टोल टूरिज्म हेल्पलाइन नंबर 0135-1364 संचालित किया जा रहा है।

चार धाम यात्रा के लिए परिवहन विभाग ने जारी की एडवाइजरी

उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा इस वर्ष 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। हर साल की तरह इस बार भी लाखों श्रद्धालुओं के गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए पहुंचने का अनुमान है। यात्रा को सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए शासन और प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में परिवहन विभाग ने चारधाम यात्रा के लिए एक विस्तृत एडवाइजरी जारी की है, जिसमें यात्रा मार्गों पर वाहन संचालन से लेकर चालकों के लिए विशेष नियम शामिल किए गए हैं। परिवहन विभाग की एडवाइजरी के अनुसार, पर्वतीय मार्गों पर रात के समय व्यवसायिक वाहनों के संचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। रात 10 से सुबह 4 बजे तक कोई भी व्यवसायिक वाहन चारधाम यात्रा मार्गो पर नहीं चल सकेगा।

एडवाइजरी में व्यवसायिक वाहन चालकों के लिए कई अन्य महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं। चालकों को विशेष प्रशिक्षण का प्रमाणपत्र, फिटनेस सर्टिफिकेट और वाहन के सभी दस्तावेज पूरे रखने होंगे। इसके अलावा, चालकों की वेशभूषा, व्यवहार और स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। एआरटीओ चक्रपाणि मिश्रा ने बताया कि यात्रा के दौरान चालकों को चप्पल या सैंडल पहनकर वाहन चलाने की अनुमति नहीं होगी। इसके बजाय उन्हें बंद जूते या मजबूत ट्रैकिंग शूज पहनना अनिवार्य होगा। यह नियम इसलिए लागू किया गया है ताकि पहाड़ी रास्तों पर वाहन संचालन के दौरान चालकों को सुरक्षा मिल सके। यात्रा के दौरान वाहनों की तकनीकी स्थिति पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। सभी व्यवसायिक वाहनों का फिटनेस सर्टिफिकेट और प्रदूषण जांच प्रमाणपत्र होना जरूरी है।

उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ फिल्म डेस्टिनेशन बनने की राह पर- सीएम धामी

पर्यटन विभाग की मदद से नए शूटिंग स्थलों को चिन्हित किया जा रहा

उत्तराखण्ड को देश का सर्वश्रेष्ठ फिल्म डेस्टिनेशन बनाने के संकल्प को दोहराते हुए सीएम श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार इस विषय में अत्यंत गंभीर है और ठोस रणनीति के साथ कार्य कर रही है। सीएम श्री धामी ने बताया कि हाल ही में हमारी सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली फिल्मो तथा वेब सीरीज को भी अनुदान देने का प्राविधान किया है। नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, सोनी लाइव, जी तथा जियो जियो हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली फिल्मो और वेब सीरीज को अनुदान देने की व्यवस्था की गई है।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को देहरादून के सिल्वर सिटी मॉल में आयोजित गढ़वाली फीचर फिल्म 'मेरी प्यारी बोई' के प्रीमियम में शामिल हुए।

फिल्म की सफलता के लिए निर्माता-निर्देशक सहित पूरी टीम को बधाई देते हुए सीएम श्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार फिल्म निर्माण से जुड़े हर क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। फिल्म निर्माण से राज्य में प्रत्यक्ष रोजगार की नई गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ ही राज्य के पर्यटन को भी नई मजबूती मिल रही है।

सीएम श्री धामी ने बताया कि पर्यटन विभाग की मदद से नए शूटिंग स्थलों को चिन्हित कर उन्हें शूटिंग के लिए बढ़ावा देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, ताकि फिल्मों के माध्यम से उत्तराखंड के अपेक्षाकृत कम प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को भी बढ़ावा दिया जा सके।

सीएम श्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड में फिल्मों की शूटिंग के लिए हर संभव मदद दी जाएगी। राज्य सरकार ने नई फिल्म नीति-2024 लागू की है, जिससे यहां फिल्म बनाना और भी आसान हो गया है। फ़िल्म निर्माताओं को फिल्मों की शूटिंग के उत्तराखण्ड भा रहा है। सिंगल विंडो सिस्टम के तहत शूटिंग की अनुमति दी जा रही है, जिससे प्रक्रिया तेज और सरल हो गई है। इसके अलावा, हिंदी और संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की फिल्मों को उत्तराखंड में व्यय राशि का 30 फीसदी खर्च या अधिकतम 3 करोड़ रुपये तक का अनुदान दिया जा रहा हा। बड़ी बजट (50 करोड़ रुपये से अधिक) और विदेशी फिल्मों पर भी राज्य में हुए खर्च का 30 फीसदी या अधिकतम 3 करोड़ रुपये तक का अनुदान मिलता है। यह योजना न केवल फिल्मों को प्रोत्साहित कर रही है बल्कि राज्य में पर्यटन को भी बढ़ावा दे रही है। राज्य की क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों के लिए राज्य में व्यय की गई राशि का अधिकतम 2 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। सीएम श्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड में शूटिंग के लिए कई खूबसूरत डेस्टिनेशन हैं। सरकार का मकसद है कि फिल्म इंडस्ट्री को बेहतर सुविधाएं देकर राज्य को फ़िल्म निर्माण का हब बनाया जाए।

सीएम श्री धामी ने कहा कि राज्य में फिल्मांकन के लिए बहुत अच्छा माहौल है। फिल्म निर्माताओं को फिल्मों की शूटिंग के लिए जनता के साथ-साथ सरकारी विभागों से भी पूरा सहयोग मिला। उत्तराखंड में फिल्मों की शूटिंग के लिए कई मनमोहक डेस्टिनेशन हैं। पहाड़ों में भरपूर प्राकृतिक सुंदरता वाले कई स्थान हैं। राज्य का हर डेस्टिनेशन फिल्मांकन के लिए उपयुक्त है। आदि कैलाश, चकराता और माणा जैसे कई आकर्षक स्थान उत्तराखंड में हैं।

उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता को देखकर देश भर से फिल्म निर्माता फिल्म शूटिंग के लिए राज्य में आ रहे हैं।

यहां फिल्मांकन की संभावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। अभी तक 200 से अधिक फिल्मों की शूटिंग उत्तराखंड में हो चुकी है। नई फिल्म नीति राज्य में फिल्मों को बढ़ावा दे रही है। बॉलीवुड के साथ-साथ स्थानीय बोलियों पर आधारित फिल्मों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

चम्पावत के कमल गिरी से लीजिए स्वरोजगार की प्रेरणा

सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर कमल गिरी बने सफल उद्यानपति

उत्तराखंड के गावों की आर्थिकी बढ़ाने के लिए औद्यानिकी बेहद जरूरी है। इसके लिए सरकार एप्पल मिशन, कीवी मिशन सहित कई योजनाएं चला रही हैं, जिसके परिणाम अब आने लगे हैं। खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में किसानों की आय बढ़ने से पलायन की समस्या का भी ठोस समाधान हो सकेगा।

पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री

आदर्श जनपद चम्पावत के निवासी 35 वर्षीय, कमल गिरी, चार साल पहले तक गांव में ही छोटी सी दुकान चलाते थे। अब कमल गिरी 35 नाली जमीन पर सेब, कीवी, आडू, खुमानी और सब्जियां उगा रहे हैं। कमल गिरी ने राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेकर, खुद को स्वरोजगार के क्षेत्र में स्थापित किया है। अब अन्य लोग भी उनसे प्रेरणा लेकर, सेब उत्पादन के लिए आगे आए हैं।

चम्पावत जिला मुख्यालय से पांच किमी दूर दूधपोखरा गांव के कमल गिरी को एक दिन सेब की जल्दी पैदावर देने वाली प्रजाति की जानकारी मिली, वो इसका पता करने के लिए भीमताल स्थित नर्सरी पहुंच गए। जहां से उन्हें उद्यान विभाग की एप्पल मिशन योजना की जानकारी मिली, जिसमें आवेदन करने के बाद उन्हें सब्सिडी पर सेब के 500 पौधे मिले। इसी के साथ उन्होंने कीवी मिशन के तहत 10 नाली जमीन में कीवी के भी पौधे लगाए। इसी तरह पांच नाली जमीन पर तेज पत्ता, बड़ी इलाईची लगाने के साथ ही मधु मक्खी पालन का भी शुरू कर दिया। बीते कुछ साल की मेहतन के बाद उनके पास अब कुल 35 नाली का उद्यान हो चुका है। जिसमें वो पॉलीहाउस के जरिए सब्जियां भी लगा रहे हैं। सहायक गतिविधि के रूप में मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन भी शुरू कर चुके हैं।

सरकारी योजनाओं का लाभ

कमल गिरी बताते हैं कि एप्पल मिशन के तहत उन्हें 60 प्रतिशत सब्सिडी पर पौधे मिले, इसी तरह 80 प्रतिशत सब्सिडी पर उन्होंने पॉलीहाउस भी बनवा लिया है। विभाग ने कीवी मिशन और तारबाड़ में भी उन्हें सहयोग दिया है। इन्हीं सब प्रयासों से जंगल के बीच में होने के बावजूद उनकी फसल जंगली जानवरों से सुरक्षित रह सकी। अब उनकी मेहनत कामयाब होने लगी है, पिछले सीजन में उन्होंने 21 कुंतल सेब बेचा, इस सीजन में कीवी का भी उत्पादन शुरू हो गया है। साथ ही 15 कुंतल तेज पत्ता भी तैयार हो गया है। पॉलीहाउस के जरिए वो नियमित सब्जियां भी बेचते हैं।

उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग

scpcr.uk

(संसद द्वारा पारित सी०पी०सी०आर० अधिनियम 2005 के अंतर्गत)

उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग बाल अधिकारों को संरक्षित करने के लिये संकलित है। 18 वर्ष से कम आयु के हर बच्चे की सुरक्षा एवं समुचित विकास हमारा दायित्व है। बाल हितों के अनुश्रवण हेतु निम्नवत कार्य निरन्तर गतिमान हैं–

- राज्य के हर बच्चे को बिना किसी रुकावट व सम्पूर्ण सुविधा सहित, शिक्षा का अधिकार अधिनियम व राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरुप उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त हो।
- किसी भी विद्यालय में विद्यार्थियों के प्रति मानसिक व शारीरिक क्रूरता पर रोक लगाने हेतु।
- सभी शारीरिक व मानसिक दिव्यांग बच्चों को भी पूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा व विकास के पूर्ण अवसर सुलभ हो।
- हर बच्चे को मिले बेहतर मानिसक व शारीरिक स्वास्थ्य सेवायें, चिकित्सकीय जॉच व कुपोषण से बचाव।
- बाल सम्बन्धी सभी राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय योजनाओं का बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को मिले लाभ एवं बाल देखरेख संस्थाओं में बच्चों को मिले बेहतर देखभाल।
- बालश्रम, बाल निक्षावृति, कूड़ा बीनने वाले बच्चों व children on street को पुनर्वासित करवाना व उनको बेहतर, शिक्षा, स्वास्थ्य व skill development के अवसर प्राप्त हों का अनुश्रवण करने हेतु।
- बच्चों को मिले शारीरिक, मानसिक व यौन शोषण और उत्पीड़न से सुरक्षा।
- बच्चों की नशे, साईबर अपराध से सुरक्षा हेतु।

नोट– शिक्षा का अधिकार अधिनियम, पोक्सो अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम, बालश्रम अधिनियम व अन्य बच्चों से सम्बन्धित कानूनों के तहत कार्यवाही का आयोग को अधिकार है। उपरोक्त वर्णित शिकायत या किसी अन्य शिकायत के लिये आयोग में सम्पर्क कर सकते हैं।

डा० गीता खन्ना, अध्यक्ष

सम्पर्क सूत्र – निकट नन्दा की चौकी, विकासनगर रोड, पो०ओ० चन्दनवाड़ी, देहरादून – 248007 (उत्तराखण्ड)

Telephone - 9258127046 (WhatsApp) Email Id: seper.uk@gmail.com/ Website: www.scpcruk.org.in

प्रधानमंत्री की नीतियों से तीस करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार की नीतियों से बीते एक दशक में देश भर में करीब 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल चुके हैं। सोमवार को देहरादून में आयोजित केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दो दिवसीय चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने यह बात कही।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारे राज्य के लिए गौरव का विषय है कि यहां सामाजिक न्याय जैसे महत्वपूर्ण विषय पर राष्ट्रीय स्तर का चिंतन शिविर आयजित किया जा रहा है। ये चिंतन शिविर बाबा साहब अंबेडकर तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे मनीषियों के चिन्तन का विस्तार भी है। इस शिविर में आयोजित होने वाले संवाद से भविष्य में अपनायी जाने वाली सामाजिक सशक्तिकरण की नीतियों का रोडमैप तैयार होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में आज देश में 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयासी के मूलमंत्र के साथ कार्य किया जा रहा है। पहले कई दशकों तक देश में समाज कल्याण विभाग कुछ गिने-चुने कार्यो तक ही सीमित माना जाता था। परंतु नरेंद्र मोदी के प्रधान सेवक बनने के बाद अपनाई गई नीतियों और योजनाओं से बीते एक दशक में देश के करीब 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आने में सफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज देश में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा एक ओर देश में बुजुर्गों, विधवाओं एवं दिव्यांगजनों को विशेष पेंशन देकर उनका जीवन स्तर सुधारा जा रहा है, वहीं छात्रों को छात्रवृत्ति देकर उन्हें अपना भविष्य उज्जवल बनाने का अवसर भी दिया जा रहा है। इसी तरह विभिन्न योजनाओं एवं नीतियों के माध्यम से स्वरोजगार और उद्यमिता को प्रोत्साहित कर अति पिछड़े वर्ग को मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। नशे की लत से पीड़ित लोगों के लिए जागरूकता कार्यक्रम और पुनर्वास केंद्रों का संचालन भी किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन से राज्य सरकार भी प्रदेश में सामाजिक न्याय की अवधारणा को धरातल पर उतारने की दिशा में कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने के साथ ही पति-पत्नी दोनों को पेंशन प्रदान कर रही है, पेंशन योजनाओं का भुगतान मासिक आधार पर किया जा रहा है, पेंशन योजनाओं को ऑनलाइन किए जाने के साथ ही अन्त्योदय परिवारों को प्रतिवर्ष तीन गैस सिलेंडर निशुल्क प्रदान किए जा रहे हैं।

इसी तरह अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के बच्चों को कक्षा 1 से लेकर बारहवीं तक छात्रवृत्ति देने के साथ ही उनके लिए निशुल्क 15 छात्रवास, 5 आवासीय विद्यालय तथा 3 आईटीआई भी संचालित की जा रही हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए नि:शुल्क कोचिंग और प्रतिमाह छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों की बेटियों की शादी के लिए 50 हजार रूपए का अनुदान भी दिया जा रहा है। जनजातीय क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास करने के साथ ही जनजातीय शोध संस्थान के लिये 1 करोड़ रुपए के कार्पस फण्ड की भी व्यवस्था की गई है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार अटल आवास योजना के तहत अनुसूचित वर्ग के आवासहीन परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए एक लाख 20 हजार रूपए की राशि प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड के 128 जनजातीय गांवों का चयन किया गया है। उत्तराखण्ड में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से वृद्धजनों के ऑखों का उपचार तथा जेरियाट्रिक केयर यानि वृद्धजनों को विशेष देखभाल की सुविधा देने के लिए लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की सरकारी नौकरियों में दिव्यांगजनों को 04 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। राज्य सरकार प्रदेश में नशामुक्त देवभूमि अभियान को मिशन मोड पर संचालित कर रही है। सरकार प्रदेश के प्रत्येक जनपद में नशामुक्ति केंद्र संचालित करने की योजना पर भी कार्य कर रही है, जनपद नैनीताल के हल्द्वानी में नशामुक्ति केंद्र का संचालन प्रारंभ भी किया जा चुका है।

राज्य में जहां एक ओर, भिक्षावृत्ति में संलिप्त बच्चों को रेस्क्यू कर उन्हें स्कूल जाने के हेतु प्रेरित किया जा रहा है, वहीं युवा एवं प्रौढ़ वर्ग के लोगों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें स्वरोजगार

से जोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है। इस दिशा में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को और अधिक मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार की इस्माइल योजना के अंतर्गत प्रदेश के चार शहरों को चयनित किया गया है। मुख्यमंत्री ने अंत में सभी प्रतिभागियों को आगामी चारधाम यात्रा पर आने का निमंत्रण देते हुए कहा कि इस साल से प्रदेश सरकार ने शीतकालीन यात्रा भी प्रारंभ की है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर्षिल में पहुंच कर प्रोत्साहित किया है।

राज्यों और केंद्र के बीच तालमेल बहुत जरूरी

इससे पूर्व, चिंतन शिविर में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ वंचित समुदाय तक पहुंचाने में राज्यों की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है। चिंतन शिविर का उद्देश्य योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाना ही है। उन्होंने बताया कि जब आगरा से चिंतन शिविर का सफर शुरू किया गया था, तब उस कार्यक्रम में सिर्फ आठ राज्यों का प्रतिनिधित्व रहा था। मात्र 12 राज्यों के अधिकारी उस कार्यक्रम में पहुंचे थे। ये शुभ संकेत है कि देहरादून के चिंतन शिविर में 15 राज्यों का प्रतिनिधित्व हो रहा है। उन्होंने नशामुक्त भारत अभियान का खास तौर पर जिक्र करते हुए कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि छात्र, युवा नशे की चपेट में आ रहे हैं। केंद्र और राज्यों को इस चुनौती से मिलकर निबटना है।

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्यमंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तुरन्त बाद चिंतन शिविर के आयोजन की खास वजह रही है। हमारा ये मानना है कि योजनाओं के ठोस क्रियान्वयन के लिए केंद्र और राज्यों के बीच शुरू में ही जानकारी साझा होने से बेहतर परिणाम निकल पाएंगे।

इस मौके पर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि हमारे पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम वंचित तबके को न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभा सकते है। प्रधानमंत्री जी ने भी सबका साथ, सबका विकास का मूल मंत्र इसीलिए दिया है। इस मौके पर कई राज्यों के मंत्री और विभागीय अधिकारी शामिल हुए।

डॉ. आर. राजेश कुमार ने चारधाम यात्रा तैयारियों को 25 अप्रैल तक पूर्ण करने के दिए निर्देश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चारधाम यात्रा 2025 की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के सचिव एवं बद्रीनाथ धाम के नोडल अधिकारी डॉ. आर. राजेश कुमार ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार, चमोली में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में उन्होंने कमेड़ा से बद्रीनाथ तक सड़क, बिजली, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं का स्थलीय निरीक्षण किया है। सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे 25 अप्रैल तक अपनी समस्त तैयारियाँ पूर्ण करें।

डॉ. राजेश कुमार ने विशेष रूप से नंदप्रयाग, कमेड़ा और पागलनाला में आगामी 15 से 20 दिनों के भीतर प्रोटेक्शन वर्क व डामरीकरण कार्य पूर्ण करने तथा नंदप्रयाग के पार्थाडीप में पुरानी गैबियन वॉल पर कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने जोगीधारा में सड़क किनारे मौजूद बड़े पत्थरों को एक सप्ताह के भीतर हटाने और हाथीपहाड़ के पास गैबियन वॉल का निर्माण जून माह तक पूर्ण करने को कहा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव स्वयं चारधाम यात्रा की तैयारियों की निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस वर्ष की यात्रा को 'हरित चारधाम' के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसके तहत सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है। सभी विभागों को इसके लिए डिस्पोजल प्लान तैयार करने को कहा गया है।

डॉ. राजेश कुमार ने अधिकारियों और कर्मचारियों से स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की अपील करते हुए नमक, चीनी और तेल के उपयोग में 10% की कमी लाने की सलाह दी।

मुख्य चिकित्साधिकारी को यात्रा मार्गो पर मेडिकल रिलीव पोस्ट की स्थापना हेतु स्थान चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। वहीं बद्रीनाथ में दीर्घकालिक पेयजल आपूर्ति के लिए जल संस्थान को दीर्घकालिक योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए गए। माणा एवलांच रेस्क्यू ऑपरेशन के सफल संचालन के लिए उन्होंने जिला प्रशासन की सराहना की।

जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने जानकारी दी कि कमेड़ा से नंदप्रयाग तक कार्य तीव्र गति से चल रहे हैं। नंदप्रयाग में रैंप विकसित किए गए हैं जिससे सड़क पर मलबा नहीं आएगा। बद्रीनाथ में बिजली और पेयजल आपूर्ति सुचारू रूप से संचालित है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विवेकानंद हॉस्पिटल, पीपलकोटी एवं बद्रीनाथ का सक्रिय सहयोग मिल रहा है। सभी आवश्यक कार्य 25 अप्रैल तक पूर्ण कर लिए जाएंगे।

डॉ. आर. राजेश कुमार द्वारा पीपलकोटी में बाढ़ सुरक्षा योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण

इसी क्रम में डॉ. आर. राजेश कुमार ने विकासखंड दशोली, नगर पंचायत पीपलकोटी के अंतर्गत मेहरगांव गधेरा, प्यूली गधेरा और अगथला गधेरा में एसडीएमएफ (राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि) के तहत प्रस्तावित बाढ़ सुरक्षा कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने इन योजनाओं को क्षेत्र की सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी और आवश्यक बताया।

60 वर्ष से अधिक बुजुर्ग, पूर्व सैनिक एवं उनकी पत्नियों तथा पूर्व सैनिकों की वीरांगनाओं और वीर नारियों को नि:शुल्क बद्री धाम की यात्रा कराई जाएगी

सैनिक वीरांगनाओं एवं पुत्रियों को ड्रोन दीदी के रूप में रोजगार परख प्रशिक्षण दिलाया जाएगा: मुख्यमंत्री धामी

मुख्यमंत्री श्री धामी ने कार्यक्रम में अपने सम्बोधन में कहा कि पांच वर्ष पूर्व आज का दिन मेरे जीवन का सबसे कष्टप्रद और दु:खद दिन रहा जब मैंने, अपने प्रेरणास्रोत पूज्य पिताजी को खो दिया। मैं, जब पूज्य पिताजी को याद करता हूँ, तो आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन गर्व भी होता है कि उन्होंने जीवन के जिन मूल्यों की मुझे शिक्षा दी, उन्हीं मूल्यों के सहारे आज मैं, जनसेवा की राह पर चल पा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि उनके पिताजी के विचार, उनके सिद्धांत और उनका संघर्षमय जीवन आज भी हर मोड़ पर मेरा मार्गदर्शन करता है। पूज्य पिताजी ने अपना संपूर्ण जीवन बड़ी ही सादगी के साथ जिया, परंतु अपने दृढ़ व्यक्तित्व और सेवा भावना द्वारा हमेशा समाज के लिए कार्य किया।

सीएम श्री धामी ने कहा कि उनके पिताजी ने सेना से रिटायरमेंट के बाद क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार प्रचार हेतु एक प्राइमरी स्कूल की स्थापना की जहां गरीब और वंचित परिवारों के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान की जाती थी। वे हमेशा कहते थे 'बेटा, देश सेवा केवल वर्दी पहनकर ही नहीं होती, बल्कि प्रत्येक क्षण अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करना भी एक प्रकार की देश सेवा ही है। उन्होंने कहा कि पिताजी के इन्हीं शब्दों ने मुझे राजनीति में कदम रखने से पहले ही ये बात सिखा दी थी कि राजनीति कोई बड़ा पद पाने का माध्यम नहीं, बल्कि जनभावनाओं को समझकर उनके दु:ख-दर्द में सहभागी बनने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए स्वयं को पूरी तरह से समर्पित कर देने का नाम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मैं, सेना में तो नहीं हूं परंतु वीर सैनिकों को अपना आदर्श मानकर राष्ट्र सेवा में अपना यथा संभव योगदान सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि एक सैनिक पुत्र होने के नाते, आज मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रक्षा क्षेत्र में हो रहे सकारात्मक बदलावों को देखकर अत्यंत हर्ष का अनुभव होता है। उन्होंने कहा कि आज भारतीय सेना को प्रत्येक क्षेत्र में सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। जिसके परिणामस्वरूप आज भारत न केवल अपनी रक्षा जरूरतों में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है, बल्कि विभिन्न देशों को रक्षा सामग्री निर्यात करने में भी नए-नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। सीएम श्री धामी ने कहा कि आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार भी सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने जहां एक ओर शहीदों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया है। वहीं, सेना में परमवीर चक्र से लेकर मेन्सन इन डिस्पैच तक सभी वीरता पुरस्कारों से अंलकृत सैनिकों को दी जाने वाली एकमुश्त तथा वार्षिकी राशि में भी अभूतपूर्व वृद्धि की है। इसके साथ ही, हमनें बलिदानियों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित करने का भी निर्णय लिया है और सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की अवधि को भी 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया है। यही नहीं, हम प्रदेश में बलिदानियों के आश्रितों को नौकरी पूर्व प्रशिक्षण तथा पुत्री विवाह अनुदान जैसी योजनाएँ भी संचालित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों और पूर्व सैनिकों हेतु सरकारी बसों में यात्रा की नि:शुल्क व्यवस्था करने के साथ-साथ सेवारत व पूर्व सैनिकों हेतु 25 लाख रुपए मूल्य की स्थायी सम्पत्ति की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में 25 प्रतिशत की छूट भी प्रदान की जा रही है।

सीएम श्री धामी ने कहा कि इन सभी कार्यों के अतिरिक्त, हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के शहीदों की स्मृति में देहरादून के गुनियाल गांव में एक भव्य सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है, जो उत्तराखंड के हमारे वीर सैनिकों की बहादुरी और बलिदान की जीवत गाथा के रूप में स्थापित होगा। हमारी सरकार द्वारा खटीमा में सैनिक मिलन केंद्र के निर्माण के साथ ही सीएसडी कैंटीन का निर्माण भी कराया जा रहा है। साथ ही, टनकपुर में आधुनिक सुविधाओं से युक्त भव्य सैनिक विश्राम गृह का निर्माण भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज इस अवसर पर सभी को आश्वस्त करता हूँ कि हमारी सरकार सेवारत सैनिकों, पूर्व सैनिकों एवं बलिदानियों के आश्रितों के हितों के लिए इसी प्रकार निरंतर कार्य करती रहेगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि सैन्य धाम जैसा एक धाम टनकपुर बनबसा खटीमा क्षेत्र में किसी एक स्थान पर जहां भूमि की उपलब्धता हो वहॉं पर सैन्य धाम का निर्माण कराए जाने हेतु कार्य किया जाए इस हेतु सैनिक कल्याण मंत्री उत्तराखंड अपने स्तर से कार्यवाही करेंगे।

इस अवसर पर कृषि एवं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इस सैनिक सम्मान समारोह में सैनिको एवं उनके परिजनों को सम्मानित करने का अवसर मिला है यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि धामी सरकार सैनिकों के कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि शहीद सैनिको के परिजनों को सरकारी नौकरी, वीरांगनाओं के पेंशन बढ़ाने का काम धामी सरकार ने किया। उन्होंने कहा कि 28 नदियों से जल व सैनिकों के घर से मिट्टी लेकर आज देहरादून में 5वां धाम सैन्य धाम बनकर तैयार हो गया है।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उपस्थित वीर नारियों, वीरगनाओं को सम्मानित किया उसके उपरांत उन्होंने चम्पावत, नैनीताल व उधमसिंह नगर के वीर शहीदों के चित्र पर पुष्ट अर्पित कर उन्हें नमन किया। उन्होंने अपने पूज्य पिता स्व0 सूबेदार श्री शेर सिंह धामी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किये। मुख्यमंत्री ने शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया।

इस दौरान केबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, सांसद अजय भट्ट, लेफ्टि0 जनरल संदीप जैन, पूर्व परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश अशोक कटारिया आदि ने भी अपने विचार रखे, तथा उपस्थित जनता को सम्बोधित किया।

इस अवसर पर दर्जा राज्यमंत्री विनय रुहेला, डा अनिल कपूर डब्बू, शंकर कोरंगा मेयर रुद्रपुर विकास शर्मा, काशीपुर दीपक बाली, हल्द्वानी गजराज बिष्ट, विधायक शिव अरोड़ा, त्रिलोक सिंह चीमा, गोपाल सिंह राणा, सुरेश गड़िया, भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज पाल, कमल जिंदल, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला, प्रेम सिंह राणा, अध्यक्ष नगर पालिका रमेश चंद्र जोशी एवं अन्य लोग मौजूद रहे।

लैब ऑन व्हील्स-मोबाइल साइंस लैब परियोजना के द्वितीय चरण का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में पढ रहे छात्र-छात्राओं को लैब ऑन व्हील्स के माध्यम से 9 मोबाईल सांइस लैब की सौगात दी गई। मुख्यमंत्री ने कैम्प कार्यालय परिसर में मोबाईल सांइस लैब के विज्ञान मॉडलों का अवलोकन किया और 09 मोबाईल सांइस लैब को हरी झण्डी दिखा कर रवाना किया। पिछले वर्ष भी मुख्यमंत्री ने राज्य के चार जिलों चम्पावत, अल्मोड़ा, देहरादून एवं पौड़ी के लिए मोबाईल सांइस लैब को हरी झण्डी दिखा कर रवाना किया था।

यूकॉस्ट के महानिदेशक प्रो0 दुर्गेश पंत ने बताया कि प्रथम चरण में राज्य के 04 जिलों क्रमशः चम्पावत, अल्मोड़ा, देहरादून एवं पौड़ी में लैब ऑन व्हील्स का सफल संचालन रहा जिसके अभूतपूर्व परिणाम को देखते हुए राज्य के शेष जनपदों में आज लैब ऑन व्हील्स का शुभारंभ किया गया। प्रो पंत ने बताया कि उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यूकॉस्ट) द्वारा राज्य सरकार की महत्वकांक्षी परियोजना के माध्यम से राज्य के ग्रामीण/दूरस्थ क्षेत्रों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और विज्ञान संचार गतिविधियों को बढावा देने का कार्य किया जा रहा है। परियोजना के अंतर्गत प्रयोगशाला, व्यवहारिक प्रदर्शनों / मॉडलों, विज्ञान गतिविधियों और प्रदर्शनों के माध्यम से प्रदेश के कक्षा छः से दसवीं तक के छात्र-छात्राओं को जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी, गणित आदि विषय के पाठयक्रम को ओर अच्छे से सीखने एवं समझ पाने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। प्रो0 पंत ने कहा कि यह प्रदेश में परियोजना का द्वितीय चरण है जिसके अंतर्गत शेष नौ जनपद उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ में किया जा रहा है।

इस अवसर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सचिव नितेश झा एवं साइंस सिटी सलाहकार जी एस रौतेला, यूकॉस्ट से संयुक्त निदेशक डॉ. डी पी उनियाल, परियोजना समन्वयक ई0 जितेन्द्र कुमार, अमित पोखरियाल, विकास नौटियाल, पुनीत सिंह एवं सहयोगी संस्था अगस्त्या इण्टरनेशनल से अमित कुमार, अशोक सिंह, योगेश के अलवा विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक राम आश्रय चौहान, निधि, शिवानी कोहली, सीमा भंडारी, अभय शर्मा, सुमन गुप्ता, अनीता नेगी एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

दून में मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए सीएम की मौजूदगी में एमओयू पर हस्ताक्षर

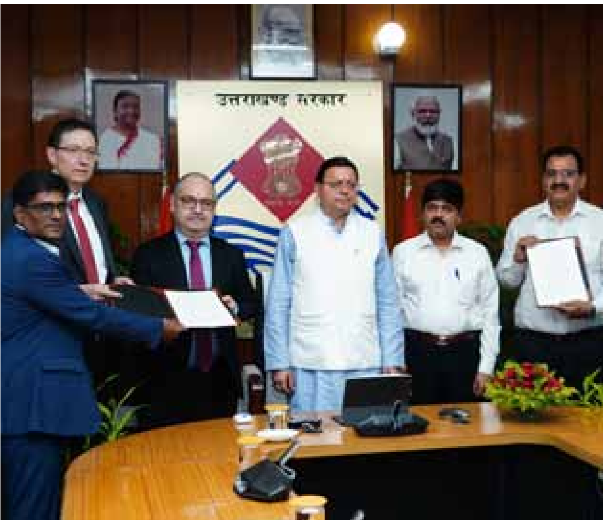

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में सोमवार को सचिवालय में मैसर्स हेस ग्रीन मोबिलिटी द्वारा उत्तराखण्ड में मास रैपिड ट्रांसिट सिस्टम तकनीक पर आधारित प्रस्तुतिकरण दिया गया। मास रैपिड ट्रांसिट सिस्टम टैक्नोजलॉजी को उत्तराखण्ड में बढ़ावा देने के मकसद से उत्तराखण्ड मेट्रो रेल कारपोरेशन एवं हेस ग्रीन मोबिलिटी, कैरोसेरी हेस एजी व एसएसबी सॉरवीन एंड शफेर बाउ एजी के बीच एक एम.ओ.यू हस्ताक्षर किया गया। मुख्यमंत्री ने इस कार्ययोजना को धरातल पर उतारे जाने की अपेक्षा करते हुए ऐसे प्रयासों को देहरादून की बढ़ती यातायात समस्याओं के समाधान के लिए जरूरी प्रयास बताया।

बैठक में बताया गया कि मैसर्स हेस एजी द्वारा लाइट ट्रॉम विकसित किया गया है, जो फ्लैश चार्जिंग तकनीक का उपयोग करते हुए एक उच्च क्षमता वाला जन परिवहन समाधान है, जिसे पूरी तरह से एलिवेटेड कॉरिडोर पर इलेक्ट्रिक रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (ई-आरटी) के रूप में उत्तराखंड की शहरी परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है तथा प्रथम चरण में देहरादून शहर के 2 कॉरिडोर्स में आई.एस.बी.टी से गांधी पार्क एवं एफ.आर.आई से रायपुर तक कुल 22.5 कि.मी, जिसमें 25 स्टेशन प्रस्तावित हैं।

बैठक में प्रमुख सचिव डॉ. आर. मीनाक्षी सुंदरम, प्रबंध निदेशक उत्तराखण्ड मेट्रो रेल कारपोरेशन श्री ब्रजेश कुमार मिश्रा, निदेशक वित्त उत्तराखण्ड मेट्रो रेल कारपोरेशन श्री संजीव मेहता, एलेक्स नेफ, सी.ई.ओ कैरोसेरी हेस एजी, बुराक सेंसर, जनरल मैनेजर एसएसबी सॉरवीन एंड शफेर बाउ एजी, यवेस सीग्रिस्ट, कैरोसेरी हेस एजी, एवं अन्य लोग मौजूद रहे।

वक्फ संशोधन विधेयक देश के गरीब मुसलमानों एवं बहनों के विकास में सहायक होगा- डॉ. बंसल

डॉ. नरेश बंसल
माननीय राष्ट्रीय सह-कोषाध्यक्ष भाजपा एवं सांसद राज्यसभा

भाजपा राष्ट्रीय सह-कोषाध्यक्ष व सांसद राज्यसभा डा. नरेश बंसल ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक बहुत सोच-समझकर आदरणीय प्रधानसेवक नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व मे सरकार द्वारा लाया गया है। यह किसी के खिलाफ नहीं है। बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग इससे संतुष्ट हैं।

डा. नरेश बंसल ने कहा कि वक्फ संशोधन का जो बिल सदन में आया है उसे कैबिनेट ने पास किया, संसद में प्रस्तुत हुआ, जेपीसी में भेजा गया, वहां विस्तार से चर्चा हुई, फिर यह बिल लोकसभा एवं राज्यसभा मे पास होने के बाद इस पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने मोहर लगाई है।वक संशोधन अधिनियम 8 अप्रैल से देशभर में लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की है कि वक्फ अधिनियम को प्रभावी कर दिया गया है।

डा. नरेश बंसल ने कहा कि इस बिल में देश के गरीब मुसलमानों के लिए सब अच्छा है। कुछ मुट्ठी भर लोगों के कैद में जो पूरा वक्फ बोर्ड रहता था उससे बाहर निकलने का रास्ता बना है। इससे कांग्रेस, सपा, टीएमसी बेचैन है। देश मे बड़े पैमाने पर निजी सम्पति, मंदिर की जमीन, तालाब, पोखर, खलिहान और ग्राम समाज की जमीनों को भी वक्फ घोषित किया गया है, जिसे सरकार ने पूरी तरह अवैध माना है। सरकारी जमीन, ग्राम समाज की जमीन और सार्वजनिक संपत्तियां किसी भी सूरत में वक्फ घोषित नहीं की जा सकतीं। केवल उन्हीं संपत्तियों को वक्फ माना जाएगा जो किसी व्यक्ति द्वारा स्पष्ट रूप से दान की गई हों।

डा. नरेश बंसल ने कहा कि मोदी सरकार के अलावा कोई ऐसी सरकार नहीं जो यह काम कर सकती थी। यह देश के लिए जरूरी था। बहुत सही समय पर यह निर्णय हुआ है। इससे मनमानी करके देश की संपत्ति पर कब्जा करने का कुछ लोगों का जो प्रयास है, उसपर प्रतिबंध लगेगा। यह कानून सरकार ने मुस्लिम गरीबों और बहनों को न्याय दिलाने के लिए लाया गया है। सरकार का यह कदम सराहनीय है।

डा. नरेश बंसल ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष के विरोध प्रदर्शनों क 'तुष्टीकरण की राजनीति' करार दिया। 2013 में पिछला कानून भू-माफिया और मुस्लिम कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए बनाया गया था। 2013 में बनाए गए वक्फ कानून से यह भ्रम पैदा हुआ कि यह अधिनियम संविधान से ऊपर है। यह कानून न्याय के लिए था, लेकिन यह डर का स्रोत बन गया। उन्होंने कहा कि नया कानून गरीब पसमांदा मुसलमानों, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करेगा व यह सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम है।

डा. नरेश बंसल ने कहा की आदरणीय प्रधानसेवक नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व मे सरकार ने इस साल के पहले 100 दिनों में अपनी नीतियों के साथ संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं। भारत अब न तो झुकने वाला है और न ही रुकने वाला है। तेज विकास के लिए शांति, स्थिरता और सुरक्षा बहुत जरूरी है। सरकार ने आतंकवाद और नक्सलवाद पर लगाम लगाई है।

सेतु आयोग द्वारा राज्य की गोल्डन जुबली 2050 तक का विजन डॉक्यूमेंट बनाया जाए- मुख्यमंत्री

राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में संभावनाओं पर विषय विशेषज्ञों द्वारा संक्षिप्त रिपोर्ट बनाई जाए

सेतु आयोग द्वारा राज्य की गोल्डन जुबली 2050 तक का विजन डॉक्यूमेंट बनाया जाए। आगामी 25 सालों में राज्य के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विकास के लिए सुनियोजित प्लान बनाकर उसका क्रियान्वयन किया जाए। प्रवासी उत्तराखण्डियों को राज्य की विकास यात्रा से जोड़ने और राज्य में निवेश के लिए उन्हें प्रेरित करने की दिशा में भी कार्य किये जाएं। सेतु आयोग द्वारा विभागों की पॉलिसी का विस्तृत विश्लेषण किया जाए और विभागों के कार्यों को बेहतर क्रियान्वयन के लिए सहयोग दिया जाए। यह बात मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में सेतु आयोग की नीतिगत निकाय की प्रथम बैठक के दौरान कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सेतु आयोग का महत्वपूर्ण योगदान होगा। सेतु आयोग द्वारा 02 वर्ष का अल्पकालिक, 10 वर्ष का मध्यकालिक और 25 वर्ष की दीर्घकालिक योजना बनाई जाए। उन्होंने कहा कि योजना बनाने के साथ ही उनके क्रियान्वयन और अनुश्रवण पर विशेष ध्यान दिया जाए। राज्य में बागवानी और डेरी क्षेत्र में कार्य की अपार संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सेतु आयोग के विशेषज्ञों द्वारा इस क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया जाए। युवाओं के कौशल विकास और आधुनिक प्रशिक्षण की दिशा में कार्य किये जाएं। उन्होंने कहा कि सेतु आयोग को विभागों के उत्प्रेरक (कैटलिस) की भूमिका में कार्य करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में संभावनाओं पर विषय विशेषज्ञों द्वारा संक्षिप्त रिपोर्ट बनाई जाए, जिससे विभागों को आगे कार्य करने के लिए सही दिशा मिले। उन्होंने कहा कि राज्य में कृषि, बागवानी, पर्यटन, ऊर्जा, औषधीय उत्पादों के क्षेत्र में कार्य करने की अनेक संभावनाएं हैं।

कैबिनेट मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर नीति बनाई जा रही है ताकि उनका धरातल पर बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हो सके। इसी का परिणाम है कि सीएम छात्रवृत्ति योजना लागू होने के बाद विद्यालयों में छात्रों की संख्या बढ़ी है। बेहतर स्वास्थ्य योजनाओं से स्वास्थ्य सुविधाओं में अनेक सुधार हुए हैं, संस्थागत प्रसव में तेजी से वृद्धि हुई है।

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के उत्पादों की मार्केटिंग बेहतर हो सके। इसके लिए सप्लाई चैन के साथ ही स्थानीय स्तर पर क्लस्टर खेती को और अधिक प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

सेतु आयोग के उपाध्यक्ष श्री राजशेखर जोशी ने अब तक आयोग द्वारा किए गए और भविष्य में किए जाने वाले कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विकसित और सशक्त उत्तराखंड की दृष्टि से राज्य की नीति कैसी होनी चाहिए, इसके लिए विभागों के साथ समन्वय कर उन नीतियों को बेहतर तरीके से क्रियान्वयन कराना सेतु आयोग का मुख्य उद्देश्य है जिससे योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति को मिल सके। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड राज्य के समग्र विकास के लिए विभागों के साथ मिलकर रणनीति तैयार की जा रही है। इससे धरातल में योजनाओं की स्वीकार्यता बढ़ेगी और क्रियान्वयन में भी आसानी होगी। तकनीकी का अधिकतम उपयोग, इकोनॉमी और इकोलॉजी में संतुलन और प्रभावी अनुश्रवण किया जाएगा। टाटा ट्रस्ट, बिल गेट्स फाउंडेशन, नैस्कॉम, आई टी सी, महिंद्रा जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर कृषि, उच्च शिक्षा, पशुपालन, स्वास्थ्य, उद्योग, कौशल विकास, आई टी व अन्य क्षेत्रों में कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य की बंजर भूमि को खेती योग्य बनाने, कृषि उत्पादक संगठन, डेयरी क्षेत्र को सशक्त करने की दिशा में कारगर प्रयास किए जा रहे है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी शत्रुघ्न सिंह ने बताया सेतु आयोग का सुचारू रूप से संचालन हो रहा है। आयोग का मुख्य उद्देश्य राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास को सशक्त बनाया है। एक माह के भीतर आयोग के कार्यों के आउटपुट राज्य के भीतर देखने को मिलेंगे।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्या, प्रमुख सचिव श्री आर मीनाक्षी सुंदरम, सचिव श्री शैलेश बगोली, श्री दिलीप जावलकर, सलाहकार वित्त हनुमंत पंत, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन विशाल पराशर, सामाजिक कल्याण भावना सहित आयोग के सदस्य मौजूद रहे।

उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए कैबिनेट सचिव तथा भारत सरकार के विभिन्न सचिवों से की भेंट

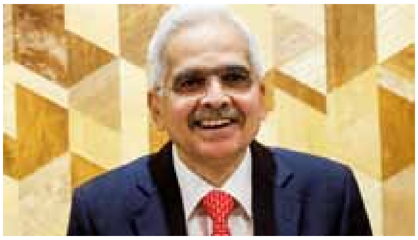

राज्य में सुगम यातायात तथा दुरुस्त कनेक्टिविटी सुदृढ़ीकरण करने के क्रम में मुख्य सचिव ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सतीश कुमार और सड़क परिवहन सचिव श्री वी. उमाशंकर तथा नागरिक उड्यन सचिव श्री वुमलुनमंग वुलनम से भेंट कर राज्य में संचालित एवं प्रस्तावित योजनाओं के विषय में वृद्धि चर्चा की। इसमें प्रमुखत: ऋषिकेश-कर्णप्रयाग परियोजना को शीघ्र संचालित किया जाना एवं अन्य महत्वपूर्ण योजना गंगोत्री यमुनोत्री रेल परियोजना, टनकपुर बागेश्वर रेल परियोजना, देहरादून-सहारनपुर रेल परियोजना तथा किच्छा-खटीमा रेल परियोजना को शीघ्र स्वीकृत हेतु अनुरोध किया। साथ ही जनमानस को बेहतर सुविधा एवं शहरों के यातायात को सुगम बनाए जाने हेतु पुराने ऋषिकेश रेलवे स्टेशन को पूर्णत: योग नगरी

रेलवे स्टेशन स्थानांतरित एवं देहरादून के हर्रावाला रेलवे स्टेशन को विकसित करने का भी अनुरोध किया।

देहरादून एवं पंतनगर हवाई अड्डों पर रात्रिकालीन लैंडिंग की सुविधा, पर्वतीय क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर की सुरक्षित संचालन हेतु केदारनाथ एवं सहस्त्रधारा में एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) सुविधाओं तथा देहरादून स्थित जौलीग्रांट एवं पंतनगर हवाई अड्डे के विस्तारीकरण में तेजी लाने का अनुरोध किया, जिससे हवाई सेवाओं में सुदृढ़ीकरण हो सके। सड़क यातायात हेतु देहरादून आउटर रिंग रोड परियोजना देहरादून-मसूरी तथा पूर्व में प्रेषित राज्य की प्रस्तावित योजनाओं पर शीघ्र अनुमति हेतु अनुरोध किया।

राज्य में ऊर्जा स्रोतों में वृद्धि तथा दूरसंचार को बेहतर बनाने के लिए ऊर्जा मंत्रालय के सचिव श्री पंकज अग्रवाल, जल शक्ति मंत्रालय की सचिव सुश्री देबाश्री मुखर्जी और दूरसंचार मंत्रालय के सचिव श्री नीरज मित्तल से भेंट वार्ता की। जिसमें प्रमुखत: से किशाऊ परियोजना, सेला उरथिंग परियोजना, बीएसएनएल द्वारा 4G टावर शीघ्र लगाए जाएं, प्रस्तावित शारदा कॉरिडोर हेतु अतिरिक्त टावर का अनुरोध किया। इसके साथ ही राज्य में हाइड्रो पावर की 2500 करोड़ रुपए तक की परियोजनाओं को राज्यस्तर पर प्रतिनिधायन तथा परियोजनाओं में त्वरित कार्रवाई हेतु अनुरोध किया।

उत्तराखण्ड राज्य के युवाओं के कौशल में वृद्धि तथा हुनरमंद नौजवानों को वैश्विक मंच तक पहुंचाने के लिए विदेश सचिव

मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल से भेंट कर राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए सीमांत क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों के विषय में अवगत कराया

प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी0के0 मिश्रा और प्रधान सचिव शक्तिकांत दास, कैबिनेट सचिव डॉ. टी.वी. सोमनाथन से शिष्टाचार भेंट की और राज्य में चल रही विकास परियोजनाओं से अवगत कराया

(सीपीवी) श्री अरुण कुमार चटर्जी और कौशल विकास मंत्रालय के सचिव श्री अतुल तिवारी से भेंट कर कार्य योजनाओं पर चर्चा की।

राज्य के विकास हेतु वाह्य विशेष सहायता एवं केन्द्रीय अनुदान तथा अन्य वित्त संसाधनों पर वित्त सचिव श्री अजय सेठ, सचिव (व्यय) डॉ. मनोज गोविल से चर्चा कर राज्य के संसाधनों की आवश्यकताओं से अवगत कराया।

इस अवसर पर स्थानिक आयुक्त श्री अजय मिश्रा भी उपस्थित रहे।

सिर्फ ट्रेलर देखकर ही... टल गई 'फुले' की रिलीज डेट, अब किस दिन पर्दे पर दिखेगी फिल्म?

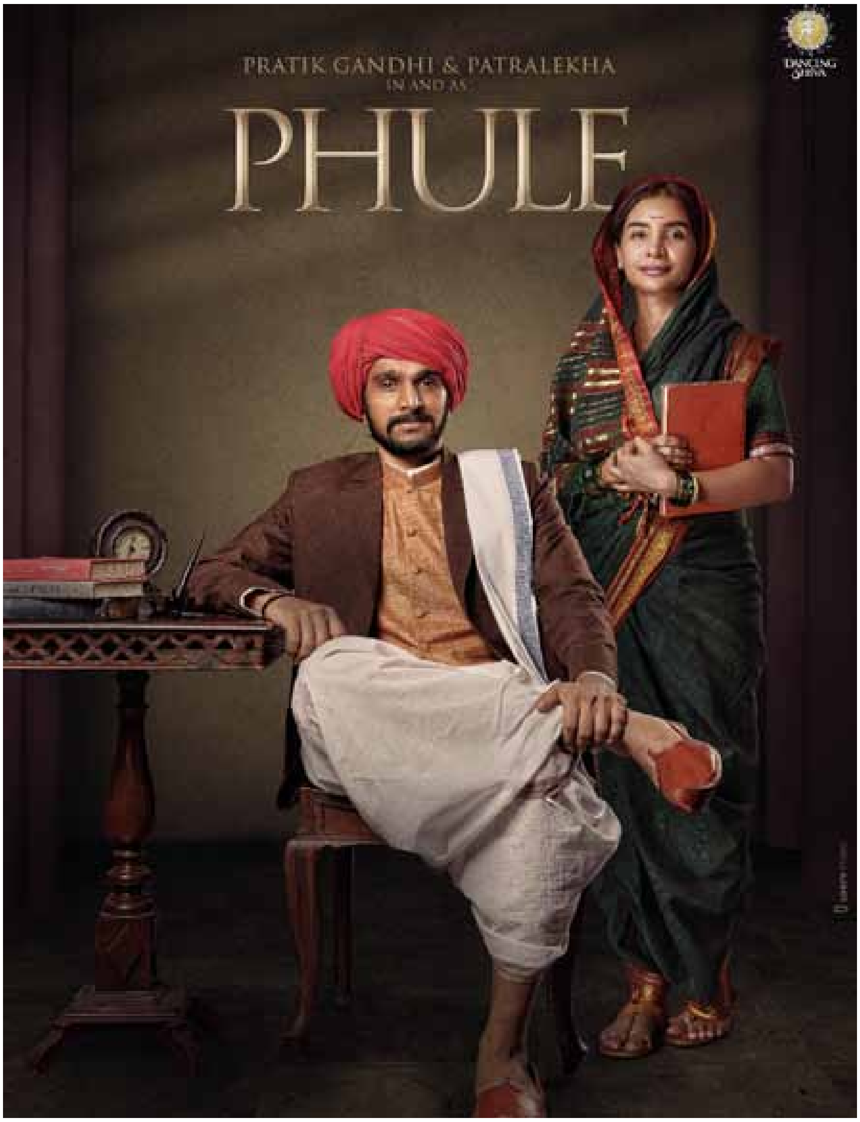

प्रतीक गांधी और पत्रलेखा की मोस्ट अवेटेड फिल्म फुले ट्रेलर रिलीज के बाद से चर्चा में आ गई। फिल्म पर जातिवाद बढ़ाने का आरोप लगा है। विवादों के कारण इस मूवी की फिल्मी गलियारों में खूब चर्चा चल रही है। इससे पहले भी कई फिल्मों पर कंट्रोवर्सी हुई है और मेकर्स को कुछ बदलाव करने पड़े हैं। फुले फिल्म (Phule) को रिलीज डेट को सिनमाघरों में दस्तक देने से ठीक एक दिन पहले बदल दिया गया है। आइए इसके पीछे का कारण विस्तार से जानते हैं।

फिल्म से जुड़े विवाद पर निर्देशक ने क्या कहा?

निर्देशक अनंत महादेवन ने न्यूज 18 को दिए हालिया इंटरव्यू में कहा, 'लोगों ने ट्रेलर देखकर फिल्म को जज किया है, जो सही तरीका बिल्कुल नहीं है। उन्होंने आगे बताया कि 'फुले की कहानी समाज की कुरीतियों पर चोट करती है, जो दिखाती है कि आज के समय में भी कई छोटे शहरों में जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है।'

फुले फिल्म की नई रिलीज डेट

अनंत महादेवन की निर्देशित फुले फिल्म पहले 11 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, लेकिन विवादों के चलते मेकर्स को रिलीज डेट में बदलाव करना पड़ा। फिल्म निर्माता की आधिकारिक घोषणा के मुताबिक, अब मूवी को 25 अप्रैल को रिलीज किया जाएगा यह फिल्म 11 अप्रैल 2025 को रिलीज होने वाली थी। खैर, अब इसे दो हफ्ते बाद यानी 25 अप्रैल 2025 को रिलीज किया जाएगा। इस मूवी का ट्रेलर देखने के बाद ब्राह्मण समाज ने नाराजगी जाहिर की और आरोप लगाया कि पत्रलेखा और प्रतीक गांधी की फिल्म जातिवाद को बढ़ावा देती है।

मेकर्स को मिले फिल्म में बदलाव करने के निर्देश

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) ने फुले के ट्रेलर को देखने के बाद मेकर्स को इसमें बदलाव करने के लिए आदेश दिए। खासतौर पर इसमें दिखाए गए जातिवाद के डायलॉग को हटाने की बात कही गई है। इसके अलावा फिल्म के कुछ शब्दों को भी हटाने के निर्देश निर्माताओं को दिए गए हैं। इसके पीछे वजह है कि फिल्म को हर वर्ग के लोगों के देखने के उपयुक्त बनाया जा सके।

प्रतीक गांधी ने लोगों की नाराजगी पर क्या कहा?

फुले फिल्म में प्रतीक गांधी लीड रोल में नजर आएंगे। एक्टर ने फिल्म पर चल रहे विवाद से पहले कहा था, 'आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती है कि लोग किसी भी बात पर नाराज हो सकते हैं। सोशल मीडिया के जमाने में हर किसी के पास कुछ भी कहने की ताकत है और कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं। ऐसी स्थिति में फिल्म से जुड़े लोगों को डरने की जगह आत्मविश्वास से काम लेना चाहिए।

R.N.I.: UTTHIN/2010/41629 Postal Regd. UA/DO/DDN/01/2025-2027

जानिए कैसा होगा आपका यह सप्ताह

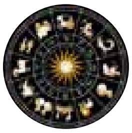
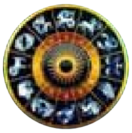
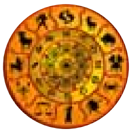

पं. दीपक प्रसाद, शास्त्री (मो. 9557730042)
(ज्योतिष, कर्मकाण्ड, धर्मिक अनुष्ठान आदि)

मेष राशि- व्यवस्थित दिनचर्या से आप कई कार्यों को अंजाम दे सकते हैं। आपकी सूझबूझ और समझदारी से पारिवारिक मामला सुलझाने में सुविधा रहेगी। करीबी संबंधी की परेशानी हल करने में आपको मदद करनी पड़ सकती है। ऐसा करने से आपको खुशी ही महसूस होगी। मन में चल रहे सवालों का जवाब खुद को तलाशना होगा। अचानक धन वृद्धि होगी।

वृषभ राशि- उत्तम ग्रह स्थिति रहेगी। अपने सपने और कल्पनाएं साकार करना चाहते हैं, तो योग्यता और कार्य क्षमता पर विश्वास रखें। बहुत सी परेशानियों का समाधान मिलेगा। कहीं रुका हुआ पैसा मिलने से आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो जाएगी। किसी भी प्रतिकूलता में घबराने के बजाय उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करें।

मिथुन राशि- कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है और उन्हें आप बखूबी निभा भी लेंगे। प्रकृति आपको कोई बेहतरीन मौका देने वाली है, लेकिन उन्हें हासिल करना आपकी योग्यता पर भी निर्भर करता है। घर की साज सज्जा की योजनाओं पर भी विचार होगा। अति आत्मविश्वास जैसी भावना अपने अंदर ना आने दे। भाग्यशाली रंग- हरा, भाग्यशाली अंक- 2

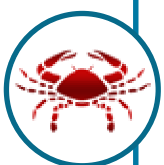

कर्क राशि- संतान को लेकर चल रही योजना साकार होने की संभावना है। लंबे समय से चली आ रही चिंता समाप्त होगी। जिससे मानसिक शांति रहेगी। आर्थिक मामले में ठोस और महत्वपूर्ण निर्णय सफल रहेंगे। भूमि या वाहन के लिए ऋण लेने का विचार बन रहा है, तो उस पर दोबारा विचार करें। घर के किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी।

सिंह राशि- पारिवारिक सुख शांति बढ़ेगी। चिंता या परेशानी आपकी सूझबूझ से हल हो जाएगी। आपकी कार्यकुशलता और योग्यता की तारीफ होगी। विद्यार्थी और युवा करियर और पढ़ाई को लेकर सावधान रहेंगे। रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों का रुझान बढ़ेगा। भावना प्रधान होने की वजह से जरा सी भी नकारात्मक बात आपको व्यथित कर सकती है।

कन्या राशि- मान-सम्मान बढ़ेगा। आपका हर काम को बहुत अधिक सोच-विचार कर करना आपको सफलता देगा। किसी मित्र की मदद से उलझे काम सुलझ जाएंगे। मानसिक रूप से बहुत सुकून महसूस करेंगे। अपनी कार्य क्षमता व योग्यता पर विश्वास रखें। युवा वर्ग भावनाओं में आकर अपना कोई नुकसान कर सकते हैं, इसलिए व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएं।

तुला राशि- घर के बड़े लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। परिवार के साथ घर की जरूरत संबंधी वस्तुओं की खरीदारी में भी समय बीतेगा। बच्चों के साथ समय बिताने से सुकून मिलेगा। निवेश सोच-समझकर ही करें। लोगों के साथ बातचीत करते समय सावधान रहें, गलतफहमियों की वजह से संबंधों में खटास आ सकती हैं।

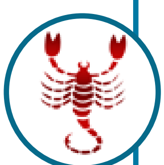

वृश्चिक राशि- ग्रह गोचर अनुकूल बना हुआ है। व्यस्तता रहेगी। आप मेहनत द्वारा अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ध्यान रखें कोई भी काम बिना योजना के न करें। घर परिवर्तन संबंधी कुछ कार्य की योजनाएं बनेंगी। ज्यादा सोचने से तनाव होगा। इससे आपकी कार्य क्षमता प्रभावित होगी। कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी हाथ से निकल सकते हैं।

धनु राशि- अनुकूल समय है। इस समय आपका कोई रुका हुआ व्यक्तिगत कार्य राजनीतिक व्यक्ति की मदद से हल हो सकता है। पारिवारिक और व्यवसायिक माहौल को और अधिक बेहतर बनाने के लिए किए गए प्रयासों में सार्थकता मिलेगी। नकारात्मक परिस्थिति को क्रोध की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से निपटाएं। भाग्यशाली रंग- बादामी, भाग्यशाली अंक- 3

मकर राशि- किसी विशेष कार्य में सफलता के लिए अपनी ऊर्जा और समय को मैनेज करें। जल्दी सफलता मिलेगी। कोई पॉलिसी या बिजनेस में निवेश करने के लिए अनुकूल समय है। सामाजिक दायरा बढ़ेगा और आप अपने व्यक्तिगत कार्यों पर ध्यान दे पाएंगे। घर में भी पारिवारिक सदस्यों के साथ किसी छोटी सी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है।

कुंभ राशि- पिछले कुछ समय से किसी कार्य के प्रति चल रहे प्रयासों के सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। शेयर्स या किसी पॉलिसी आदि में निवेश करना लाभदायक रहेगा। परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का प्रोग्राम बन सकता है। किसी को भी मदद करने का प्रॉमिस करते समय अपने सामर्थ्य का भी ध्यान रखें। भाग्यशाली रंग- बादामी, भाग्यशाली अंक- 2

मीन राशि- कई तरह की गतिविधियां आपको व्यस्त रखेंगी। सामाजिक तथा पारिवारिक लोगों की तरफ से विशेष मान-सम्मान भी मिलेगा। घर में रिश्तेदारों के आगमन से किसी खास मुद्दे पर सकारात्मक विचार-विमर्श भी होगा। विद्यार्थी नए सत्र की पढ़ाई को लेकर उत्साहित रहेंगे। कुछ रिश्तेदार आपके व्यवहार से परेशान हो सकते हैं।